दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 मंगलवार, 24 फरवरी, 2015/फाल्गुन 05, 1936(शक) अंक-02

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे आरम्भ हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः-

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह
9. श्री रितु राज गोविन्द
10. श्री राघवेन्द्र शौकीन
11. कु. राखी बिड़ला
12. श्री बिजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
15. श्री सोम दत्त
16. कु. अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. स. जरनैल सिंह
23. स. जगदीप सिंह

24. स. जरनैल सिंह
25. श्री राजेश ऋषि
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री नरेश बाल्यान
28. श्री आदर्श शास्त्री
29. श्री गुलाब सिंह
30. श्री कैलाश गहलोत
31. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
32. कु. भावना गौड़
33. श्री सुरेन्द्र सिंह
34. श्री विजेन्द्र गर्ग विजय
35. श्री प्रवीन कुमार
36. श्री मदन लाल
37. श्री सोमनाथ भारती
38. श्रीमती प्रमिला टोकस
39. श्री नरेश यादव
40. श्री करतार सिंह तंवर
41. श्री प्रकाश
42. श्री अजय दत्त
43. श्री दिनेश मोहनिया
44. श्री सौरभ भारद्वाज
45. श्री अवतार सिंह कालका
46. श्री सही राम
47. श्री नारायण दत्त शर्मा
48. श्री अमानतुल्ला खान
49. श्री राजू धिंगान
50. श्री मनोज कुमार
51. श्री नितिन त्यागी
52. श्री ओम प्रकाश शर्मा
53. श्री एस.के. बग्गा
54. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
55. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
56. श्रीमती सरिता सिंह
57. चौ. फतेह सिंह
58. श्री हाजी इशराक
59. श्री श्रीदत्त शर्मा
60. श्री जगदीश प्रधान
61. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-01 मंगलवार, 24 फरवरी, 2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) अंक-02

सदन पूर्वाहन 11.25 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत-वन्दे मातरम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि सचिव, दिल्ली विधान सभा माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखें, मैं माननीय सदस्यों को कुछ दो-तीन बातें उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक तो नये सदस्य हैं, इसलिये उनको धीरे-धीरे सभी को जानकारी हो जायेगी। सदस्य किसी को भी इधर क्रास करना है या अपनी सीट पर जाना है तो कृपया सदन के वैल से क्रॉस न करें। ये सदन की मर्यादा होती है। वैल में हम बिल्कुल नहीं आयेंगे। और विशेषकर सत्तापक्ष के बन्धुओं को सदन के वैल में बिल्कुल नहीं आना चाहिये।

दूसरी बात, कोरम का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है 1/3 से कोरम कभी भी डाउन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सदन को स्थगित करना पड़ता है। तीसरी मेरी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी दर्शक यहाँ आते हैं, हम ही उनको पास के लिए साइन करके देते हैं। कल पहला दिन था, कोई बात नहीं, वो आये, देखे, सुने लेकिन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किसी के भाषण पर, वक्तव्य पर वो व्यक्त न करें। न clapping करें, न hooting करें, दर्शक आज जो

बैठे हैं, मैं उनसे भी यह निवेदन कर रहा हूँ और भविष्य में जब भी आगे सदन होगा हम पास देने से पहले, साइन करने से पहले माननीय सदस्य उनको इस बात की जानकारी दे दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात

अध्यक्ष महोदय : अब सचिव, विधान सभा उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिन्दी-अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण की हिन्दी अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष एवं आदरणीय सदस्यगण,

मैं, दिल्ली की छठी विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मेरी सरकार बहुत आशावान है और हम विनम्रतापूर्वक दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। यह ऐसा जनादेश है जिससे जाति, पंथ और धर्म से हटकर युवाओं एवं वृद्धों, गरीब तथा अमीर, पुरुषों और महिलाओं के सपने एवं आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। जनता ने यह जनादेश एकजुट होने के लिए प्रबल संदेश के रूप में दिया है। जनता को ऐसा सुशासन चाहिए जो स्वच्छ राजनीति के उभर कर आया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए अपनी आकांक्षाओं को प्रकट किया है। दोषदर्शिता के युग में उन्होंने भागीदारी और परामर्श लोकतंत्र के ऐसे एक मात्र राजनैतिक सिद्धान्त में अपना विश्वास प्रकट किया है जिससे पूर्ण स्वराज अर्थात्

स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। मेरी सरकार का इरादा है कि रोजमर्रा की ऐसी समस्याएं जो जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं उनमें जनता को शामिल करके लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान की जा सके। मेरी सरकार समय के साथ-साथ निर्वाचक और निर्वाचित के बीच पैदा हुई दूरी को समाप्त करना चाहती है।

मेरी सरकार का विश्वास है कि सुशासन में समाज के सभी वर्गों की चिन्ताएं प्रदर्शित होनी चाहिए। साथ ही विकास में प्रत्येक नागरिक की भलाई शामिल हो अर्थात् विकास समेकित होना चाहिए। दिल्ली को सुरक्षित और प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य जो इसे संसार की सबसे अच्छे राजधानी शहरों में स्थापित कर सके, तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक यहां का प्रत्येक नागरिक अपनी आजीविका, जीवन शैली और धार्मिक विश्वास के अनुसार सुरक्षित महसूस कर सके। यही दिल्ली की जीवन शैली है और यही भारत देश की परिकल्पना का आधारभूत तत्त्व है।

मेरी सरकार का प्रयास है कि वह पारदर्शी, सहभागिता और परस्पर सहयोग पर आधारित हो। हमारा भरपूर प्रयास होगा कि भ्रष्टाचार के मामलों की समयबद्ध जाँच करवाने के लिए दिल्ली में जन-लोकपाल की स्थापना की जाए। भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

दिल्ली के लोगों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के महत्त्वपूर्ण प्रयास के रूप में मेरी सरकार स्वराज अधिनियम बनाएगी जिससे स्थानीय जन समूह को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में अहम भूमिका प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय जन समुदायों को नागरिक स्थानीय विकास निधि (सी-लैड) प्रदान की जाएगी।

मेरी सरकार का इरादा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर अधिकाधिक बल दिया जाए। दिल्ली के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है। यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य के रूप में स्वायत्तता प्रदान की जाती है तो कानून व्यवस्था, सस्ते मकानों जैसी महत्त्वपूर्ण जन सेवाओं को मुहैया कराने में सरकार का अधिक नियंत्रण रहेगा। आशा है कि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक रूप से घोषित सहयोग आधारित संघवाद की नीति को बढ़ावा देने के विचार से दिल्ली के शासन को वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी और तब दिल्ली में विभागों की बहुलता और अधिकार क्षेत्रों की विषमता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

इन सभी का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस जैसे संस्थान दिल्ली की निर्वाचित सरकार के प्रति जवाबदेह हों। नागरिक सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने से सरकार तथा जनता के बीच की दूरी को कम करने में मदद मिलेगी।

पिछले कार्यकाल की तरह ही, इस बार भी मेरी सरकार मूलभूत जन-सुविधाओं जैसे बिजली एवं पानी के इस्तेमाल करने के आर्थिक बोझ को कम करने की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगी। जो नीतियां बनाई जाएंगी उनसे न केवल उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास पहले से ये सुविधाएं हैं। बल्कि उन कॉलोनियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्हें मूल रूप से बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

जन सेवाओं के लिए खर्च करने की क्षमता की दृष्टि से यह बताना उचित होगा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अधिक संसाधन जुटाने की दिल्ली की अपनी अन्तरनिहित क्षमता है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली राज्य के

सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिल्ली का बजट अधिशेष रहने का भी पुराना इतिहास है। इस वित्त वर्ष में दिल्ली का कुल बजट लगभग 37,000 करोड़ रुपये है। यदि अधिकतम उपयोग किया जाए तो विकास का एक नया ब्लू प्रिन्ट तैयार किया जा सकता है। इस निधि को ईमानदारी और कुशलता से इस्तेमाल करना ही समग्र विकास के प्रति हमारे संकल्प को पूरा करने की कुंजी होगी। नागरिकों को मूलभूत जन-सुविधाओं से विहीन रखा गया इसके पीछे कभी धन की कमी नहीं थी। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ये सेवाएं गरीब जनता को यथार्थ रूप से कितनी ईमानदारी और कुशलता से प्रदान की जा रही हैं। मेरी सरकार भरसक प्रयत्न करेगी कि संसाधनों की लेखा परीक्षा करवाई जाए ताकि यह पता चले कि बिजली या पानी या अन्य जन सेवाओं को प्रदान करने के क्षेत्र में कहां क्या कमी है। हम आश्वस्त हैं कि दिल्ली को आधुनिक और समृद्ध राजधानी नगर के रूप में रूपान्तरित करने के लिए इसके पास अपने पर्याप्त संसाधन हैं, जहां प्रत्येक नागरिक अपना विशेष स्थान बना सकता है।

मेरी सरकार अपने इस वचन के प्रति भी सचेत है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य बने जहां महिलाएं घरों में और अपनी आजीविका कमाने तथा सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए तनावमुक्त महसूस करें। मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था करने में धन की कमी नहीं होने देगी। मेरी सरकार आवागमन की दृष्टि से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अंतिम छोर तक सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि महिलाएं सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें। मेरी सरकार न्यायालयों में निर्णयों में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, जो विशेष तौर पर यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए होगी। होमगार्ड तथा सिविल डिफेंस वालेन्टियर्स को तैनात करके

महिला सुरक्षा दल बनाए जाएंगे। इसके अलावा मेरी सरकार नए जजों की नियुक्ति के लिए भी पूर्ण प्रयास करेगी ताकि न्यायिक तंत्र तीव्र और प्रभावी हो सके।

हमारे मत के अनुसार दिल्ली को उत्कृष्ट डिजिटल राजधानी शहर बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए हमने दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई हॉट-स्पॉट तैयार करने की महत्त्वपूर्ण योजना तैयार की है। इससे शिक्षा, उद्योग, व्यापार तथा रोजगार और साथ ही महिला सुरक्षा संबंधी प्रयासों को विशेष बल मिलेगा।

उत्कृष्ट राजधानी शहर बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती और विस्तार प्रदान करेगी। दिल्ली के प्रत्येक बच्चे को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए नए स्कूल बनाए जाएंगे और सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नर्सरी में प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम से कम किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ऐसी स्कीम बनाने के लिए प्रत्यनशील है कि प्रत्येक युवक डिप्लोमा या डिग्री स्तर के कोर्स आसानी से कर सके, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आएगी। हम दिल्ली के लोगों के साथ भागीदारी करके दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत नए कॉलेज बनाएंगे। दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आने वाले कॉलेजों की वर्तमान दाखिले की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसमें दिल्ली का अग्रणी विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी शामिल है।

मेरी सरकार स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संरचनागत इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बजट की राशि में बढ़ोतरी करेगी। सरकार नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

करेगी तथा दिल्ली के अस्पतालों में विशेषकर मैटरनिटी वार्डों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अच्छी दवाइयाँ उचित कीमत पर मुहैया कराई जाएंगी तथा दवाईयों एवं उपकरणों की खरीद के काम को केन्द्रीकृत करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा।

ऐतिहासिक रूप से दिल्ली ऐसा नगर रहा है जिसमें व्यापार फलता-फूलता है और मेरी सरकार भी इसको व्यापार और खुदरा बाजार का केन्द्र बनाने के लिए वचनबद्ध है। जिसके लिए व्यापारियों के लिए आसान कर प्रणाली तैयार की जाएगी। सरकार अपने इस संकल्प के प्रति भी दृढ़ है कि दिल्ली को इंस्पैक्टर राज से मुक्त किया जाए। हम व्यापारियों पर छापेमारी को कम करेंगे। व्यापारियों और सरकार के बीच परस्पर समन्वय के लिए आपसी विश्वास को महत्त्व देंगे। हम ऐसी नीति का निर्माण करना चाहते हैं जिससे देश का प्रत्येक व्यापारी और महिला उद्यमी दिल्ली आकर अपना कारोबार स्थापित करना चाहेगा।

मेरी सरकार की महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं में दिल्ली के गांवों की दशा भी है, जिन्हें पिछले सालों में उपेक्षित रखा गया है। मेरी सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि इन जगहों पर निवास करने वाले लोगों को भी खुशहाली और प्रगति के अवसर प्राप्त हों। दिल्ली के गांवों के विकास संबंधी फैसले उनकी सहमति से लिए जाएंगे। कृषि तथा पशु पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन और आधारभूत सहयोग दिया जाएगा। युवाओं को खेल-कूद के क्षेत्र में जाने के लिए गांवों में खेल-कूद सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली देहात क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुगम बनाने के लिए बस तथा मेट्रो की सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।

दिल्ली को ऐसा राज्य बनाया जाये जिसमें प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखा जाए, इसके लिए मेरी सरकार अगले पाँच वर्षों में नई नौकरियों के अवसर पैदा

करेगी। उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार नवीन और निजी उद्यम प्रारम्भ करने वालों के लिए सार्थक वातावरण तैयार करेगी। ऐसा वातावरण निर्माण करने पर ध्यान दिया जाएगा जिससे निजी उद्योग अधिक से अधिक नौकरियां प्रदान कर सके। इस विचार के अनुसार मेरी सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करेगी। दिल्ली सरकार ऐसे व्यापार प्रशिक्षण केन्द्रों का भी निर्माण करेगी जो महँगे नहीं होंगे।

पिछली सरकारों ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की अनेक घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं से आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार पुनर्वास कॉलोनियों और स्लम क्षेत्रों को दिल्ली के विकास के दायरे में शामिल करते हुए, इसे सही अर्थों में विश्वस्तरीय और आधुनिक राजधानी नगर बनाने के लिए दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अधिक यथार्थपूर्ण और प्रभावी कदम उठाएगी।

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, मैंने अगले पाँच वर्षों के दौरान दिल्लीवासियों के लिए मेरी सरकार के इरादों और कार्य योजनाओं का संक्षिप्त खाका प्रस्तुत किया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको इस सद्प्रयास में सफलता प्राप्त हो।

जय हिन्द।

Respected Speaker and Honurable Members, I warmly welcome you all to the first session of the Sixth Legislative Assembly of Delhi.

It is with great humility and profound hope that my Government accepts the mandate given to it by the people of Delhi. It is a mandate that carries the dreams and aspirations of young and old, poor and rich, women and men, regardless of caste, creed or religion. There is one unifying, resounding message that the people have sent out. They want good governance that emerges out of clean politics and to achieve with the political process. In an age of cynicism they have put their faith in the political philosophy of participative and consultative democracy that alone can lead us to Purna Swaraj that is, self. My Government intends to deepen and strengthen our democaracy by involving people in issues that affect them on a daily basis. My government will dismantle the barriers that have come up between the elected and the electors.

My government believes that good governance should reflect the concerns of all sections of society. Equally, development must include the well-being of every citizen-that is, it must be inclusive. The goal of a safe and progressive Delhi that can hold its own amongst the best capital cities of the world cannot be achieved unless each and every citizen feels safe to pursue their livelihood, their way of life and faith. For that has been Delhi's way. Indeed, that is the essence of the idea of India.

My government shall endeavour to be transparent, participative and interactive. We will make every effort to establish the Janlokpal in Delhi to ensure a time-bound investigation in corruption cases. Whistleblowers shall be provided protection from harassment.

In a major move toward devolution of power to the people, my government shall seek to legislate the Swaraj Act so as to enable the local communities to have a say on issues affecting their daily lives. For this purpose a Citizen Local Area Development (C-LAD) Fund will be provided to local communities.

Further, it is the intention of my government to push for full stathood for Delhi, which has been a long-standing demand of the people of Delhi. The provision of critical public services such as law and order and low-cost housing would happen more smoothly if Delhi were accorded autonomy as a full-fledged state with greater control over these aspects. The Centre's publicly stated position of promoting cooperative federalism will hopefully help in securing genuine autonomy for Delhi's governance. Only then can the problems created by a multiplicity of authorities and jurisdictions in Delhi be solved.

The ultimate aim is to ensure that institutions such as the DDA, MCD and Delhi Police are accountble to the elected government of Delhi. This will help bridge the gap between the govrnment and the people by creating greater coordination among civic services with regard to service delivery.

Just as in its earlier tenure, this time too my government will be responsive to the need for lowering the crushing burden of accessing besic public utilities such as power and water. The policies framed will not only benefit those who already have access to these facilities, they will pay special heed to colonies that have been deprived of formal electricity and water connections.

As for the capacity to fund public services, it may be pointed out that Delhi inherently has the potential for raising higher resources due to its robust economy. In fact the Delhi State GDP in recent years has grown impressively at several percentage points above the national average. Delhi has also had a history of budeget supluses. This financial year Delhi has a total budget of around Rs. 37,000 crore wich, if used optimally, can truly create a new plueprint of development. How effectively and honestly these funds are deployed is the key to meeting our commitment of inclusive and holistic development. It is not a paucity of funds that has kept the citizens bereft of basic public services. The crucial question is this: how effectively are those services being delivered on the ground to the very poor. My government will rigorously do a resource audit whether it is in the area of providing electricity of water or other public services. We are convinced that Delhi has enough resources to transform it in to a modern and prosperous capital city where every citizen finds a space for herself of himeslf.

My government shall be unwavering in its commitment to ensuring that Delhi remains a state where women feel as much at home and at ease as men in pursuing their livelihood and social pursuits-proudly leading from the front. My goverment will not let any fund crunch come in the way of putting in place safety and security measures for women. As regards mobility, my government will exert itself to provide effective last mile connectivity in Delhi's public transit system to ensure that its women are able to travel safely and securely. To ensure speedy justice, my government will creat fast-track courts dedicated to handling cases of exsual assault and other crimes against women. It will create a Mahila Suraksha Dal by redeploying members of the Home Guard and Civil Defense Volunteers. Further, my government will facilitate appointment of new judges to ensure that the judicial system works fast and effectively.

In line with our idea of making Delhi a digital capital city par excellence, we have an effective plan to create Wi-Fi hotspots at various public locations in Delhi. This will also provide an impetus to education, entrepreneurship, business and employment as well as tie in with women's safety initiatives.

To further this end of a capital city of excellence, my government will focus on strengthening and expanding educational and health infrastructure. It will build new schools with a special focus on secondary and senior secondary shools to ensure that every child in Delhi has

easy access to streamline the nursery admission process, minimizing avenues of corruption. In the sector of Higher Education my government will make every youth can pursue a diploma or degree course regardless of his or her financial status. We will build new colleges under Delhi administration in partnership with the people of Delhi. The existing seat capacity of Delhi government administered colleges will be cnhanced, including at Delhi's flaship university, the Ambedkar University.

My government will increase the budgetary allocation on healthcare infratructure. My government will buld new primary Health Centers (PHCs) and add new bed to Delhi hospitals, especially in meternity ward. Qulity drugs will be provided at an affordable price-pharmaceutical drug and equipment procurement will be centralized to cut out corruption.

Historically, Delhi has been a city of flourshing trade and my government is committed to making it a trade and tetail hub once again by creating a friendly tax environment for traders. The goverment is firm on its commitment to insulate Delhi's traders from the inspector raj. We will discourage raids on traders and creats a bound of trust between them and the government. We want to create a policy framework in the country would like to come to Delhi to establish new enterprises. An important priority of my government concerns Delhi's villages which over the years have become islands of neglect. My

government will take step to ensure that the people living in these spaces are able to partake the fruits of growth as well. Decisions regarding the development of Delhi's villages will be taken with their consent. The sectors of agriculuture and animal husbandry will receive incentives and infrastructural support. We shall seek to provide sports facilities in villages to encourage young adults to pursue sports. Connectivity to rural Delhi will be enhanced through increased bus and metro services.

In its effort to make Delhi a state that reaches out to its last citizen my government will create opportunities for new jobs in the next five years. The government will create an anabling environment for innovative and private startup accelerators to provide support to entrepreneurs. The focus will be on creating an ecosystem that enables private industry to create more jobs. In line with this idea, my goverment will encourage startup by setting up business and technology incubators in universities and colleges. Delhi government will also creat affordable business incubation space.

In the past, earlier gorvernments made announcements regularizing unauthorised colonies. Moving forward from these announcements, my government will take a more realistic and effective approach to regularise unauthorised colonies in Delhi, transforming resettlement colonies and slums, bringing them within the ambit of Delhi as a truly global and modern capital city.

Honourable Speaker and Members, I have presented a brief sketch of my government's intent and action plan to return Delhi to the people over the next five years. I wish you all success in this fruitful endeavour.

Jai Hind.

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : सदन लगभग एक वर्ष बाद आरम्भ हुआ है, इस अंतराल में इस सदन के माननीय तीन सदस्यों का स्वर्गवास हुआ। मैं उनका जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। सर्वप्रथम श्रीमान जनार्दन गुप्ता जी।

बड़े शोक का विषय है कि पूर्व महानगर पार्षद श्री जनार्दन गुप्ता जी का गत 01 अगस्त, 2014 को निधन हो गया। श्री जनार्दन गुप्ता 1958 में दिल्ली नगर निगम के सदस्य थे तथा 1966 व 1970 में दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1966 में वे सदन में अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे एवं 1970 में दिल्ली महानगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे। श्री जनार्दन गुप्ता अपने जीवन काल में कई महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहे और उन्होंने अपना जीवन निरन्तर जनता को समर्पित किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी वे कई महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े हुए थे।

मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री जर्नादन गुप्ता को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें व उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहने की ताकत दें।

आउम् शांति, शांति।

दूसरे, पूर्व महानगर पार्षद श्री अमरनाथ मल्होत्रा जी हमारे मध्य में नहीं रहे। बड़े शोक का विषय है कि दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व सदस्य रहे श्री अमरनाथ मल्होत्रा का 18 जनवरी, 2014 को निधन हो गया। श्री अमरनाथ मल्होत्रा दूसरी महानगर परिषद (1977-1980) में महानगर परिषद के सदस्य चुने गये। वे 1965 से राजनीति में सक्रिय थे और राजधानी के विकास के लिये कार्य करते थे।

मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री अमरनाथ मल्होत्रा को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें व उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की ताकत दें।

ओउम् शांति, शांति।

पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार वैद्य जी भी हमारे बीच में नहीं रहे। बड़े शोक का विषय है कि चौथी दिल्ली विधान सभा (2008-2013) के सदस्य श्री सुनील कुमार वैद्य का 17 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया। श्री वैद्य त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री वैद्य दिल्ली विधान सभा की गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। सदन में क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के मामले में वे हमेशा आगे रहते थे। जब-जब विपक्ष सरकार को घेरने की पहल करता, श्री वैद्य हमेशा आगे रहते थे। विधान सभा की कार्यवाही को लेकर उनकी गम्भीरता का आलम यह था कि यदि कोई आपस में बात करता था तो वह उसे टोकते थे और कहते थे कि यह वक्त आपस में बात करने का नहीं है बल्कि जनता की आवाज उठाने का है। उन्होंने हरेक क्षेत्र में अपने कार्य की छाप छोड़ी। सदन की समितियों की बैठकों में भी वे बढ़-चढ़ कर भाग लेते थे और अपने विचार रखते थे।

मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री सुनील कुमार वैद्य को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें व उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की ताकत दें।

ओउम् शांति, शांति।

इन तीनों शोक प्रस्तावों पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, अपना शोक संदेश प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने बताया श्री जनार्दन गुप्ता जी, पूर्व सदस्य महानगर परिषद, श्री अमरनाथ मल्होत्रा जी, पूर्व सदस्य महानगर परिषद और श्री सुनील कुमार वैद्य जी जो कि चौथी विधान सभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्य थे, इन तीनों के निधन पर मैं अपनी ओर से, दिल्लीवासियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से शोक व्यक्त करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। इनके परिवार को इस शोक की घड़ी में इसे सहन करने की क्षमता दें। इन तीनों का अपने-अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सुनील कुमार वैद्य जी इसी विधान सभा के सदस्य थे, वो समय-समय पर अपनी विधान सभा की समस्याओं को विधान सभा में उठाते रहे, अपनी विधान सभा के अंदर कार्य करते रहे, उन्होंने सदन की कमेटियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह से श्री जनार्दन गुप्ता जी, श्री अमरनाथ मल्होत्रा जी ने भी दिल्ली के विकास और दिल्ली वालों की समस्याओं को लेकर काफी काम किया। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति मिले।

ओउम् शांति।

अध्यक्ष महोदय : श्री बिजेंद्र गुप्ता जी।

श्री बिजेंद्र गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, अत्यंत दुःख के साथ इस सदन के समक्ष पूर्व तीन सदस्यां को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। श्री जनार्दन गुप्ता, जिनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं वर्षों तक जुड़ा रहा। एक बहुत ही दबंग और सिद्धांतों पर चलने वाले एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं। एक लम्बा बेदाग सार्वजनिक जीवन, कर्मशील, क्रियाशील सार्वजनिक जीवन और परिस्थितियों से समझौता न करना यह हमेशा उनसे सीखने का अवसर हमको मिला है। श्री

अमरनाथ मल्होत्रा जी जो 1977 में सदस्य चुने गये थे और उसी दौरान इमरजेंसी को भी इनको झेलना पड़ा था। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। श्री सुनील कुमार वैद्य जो समय के क्रूर हाथों ने, समय से पूर्व उनको हमारे बीच में से, वो चले गये बहुत होनहार एक ऐसे युवक थे जिन पर हमारी पार्टी नाज कर सकती थी। मात्र 47-48 वर्ष की आयु में अचानक सामाजिक कार्यों के लिए निकले हुए थे और वहीं पर मंच पर ही उनकी मृत्यु हो गई, परिवार में जो सदस्य हैं, न सिर्फ उनको बल्कि पूरे क्षेत्र को आघात लगा और लोगों को लगा कि एक युवा जो अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाला एक पढ़ा-लिखा युवक अचानक हमारे बीच में चला गया। मेरी उनसे घनिष्ठ मित्रता थी। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। तीनों महानुभाव जिनका स्वर्गवास हुआ है मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने दोनों सदस्यों की तरफ से ईश्वर से यह कामना करता हूँ कि इन तीनों महान आत्माओं से प्रेरणा लेकर समाज आगे बढ़ेगा और यह सदन के सदस्य भी निश्चित रूप से इन तमाम परिस्थितियों में इन तीनों सदस्यों से प्रेरणा लेंगे।

ओउम् शांति, शांति, शांति।

अध्यक्ष महोदय : अन्य कोई सदस्य भी अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं तो कर सकते है।

श्री मनीष सिसोदिया (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज हम जिन तीन साथियों को याद कर रहे हैं, स्व. श्री जनार्दन गुप्ता जी, स्व. श्री अमरनाथ मल्होत्रा जी और स्व. श्री सुनील कुमार वैद्य जी। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं, जिन्होंने इस विधान सभा को यहां पर पहुँचाने में योगदान दिया है। दिल्ली में जब ये परिकल्पना की गयी होगी कि दिल्ली की एक अपनी चुनी

हुई सभा हो। वह सभा चाहे महानगर परिषद के रूप में हो, चाहे विधान सभा के रूप में हो, उससे एक executive निकले, वह सरकार के रूप में काम करे। इन सब साथियों का प्रयास इस दिशा में काफी सराहनीय और विशेष तौर पर श्री जनार्दन गुप्ता जी और श्री अमरनाथ मल्होत्रा जी जो उस समय सदन में आसीन रहे, सदन में बैठे, जिस वक्त दिल्ली में इतने व्यापक रूप में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और दिल्ली को एक राज्य के रूप में देखने का जो सपना था, वो बहुत दूर की चीज लगता था और आज जब हम यहां दिल्ली विधान सभा में बैठे हैं, तो इन सब लोगों का निश्चित रूप से उसमें योगदान रहा है। तभी ये चीजें इन्वाल्व होकर यहाँ तक आई हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्री सुनील कुमार वैद्य जी से क्योंकि मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत रूप से भी मिला। मुझे बार-बार टी.वी. कार्यक्रमों में भी मिलने का अवसर मिला, जिस विधान सभा क्षेत्र/पटपड़गंज से मैं निर्वाचित होकर आता हूँ, उसके ठीक बाजू में त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर वे पहले आते रहे, उनसे कई बार मिलने का मौका मिला और उनका उत्साह और उनकी स्थिति और उनकी तमाम चीजों से/बातचीत से जो समझ में आता था, यही समझ में आता था कि कहीं न कहीं उनके मन में व्यवस्था को लेकर कुछ नाराजगियाँ हैं, वह उससे उलझते हुए भी दिखाई देते थे। तो आज इस सदन मे मैं इन तीनों सदस्यों के प्रति, तीनों महानुभावों के प्रति पूरे सदन की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के लोगों को, उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को शक्ति दें कि इनके न होने की स्थिति में वे इनको याद रख सकें और सूक्ष्म रूप में अपने आस-पास इनको महसूस कर सकें। ओउम शांति।

अध्यक्ष महोदय : सचिव, विधान सभा से कहूंगा कि तीनों दिवंगत आत्माओं के परिवारों को सदन की भावनाएं लिखित रूप से प्रेषित करें।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम सभी खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभा माननीय सदस्यों ने अपने आसन से खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गोपाल राय, माननीय विकास एवं परिवहन मंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 को विधान सभा में दिए गए अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। श्री गोपाल राय जी बैठकर के ही अपना सम्बोधन दें।

श्री गोपाल राय (विकास एवं परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं आज सदन में उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 को विधान सभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस सदन के अंदर निर्वाचित होकर आये हैं, उन सब लोगों का सबसे पहले इस सदन में स्वागत करना चाहता हूँ और खास तौर से दिल्ली की जनता को तहेदिल से बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति की इस ऐतिहासिक परम्परा में दिल्ली के लोगों ने एक राजनैतिक क्रान्ति दिल्ली के अंदर घटित की है। इस सदन के अंदर परम्परागत राजनीति की जितनी जड़ता थी, उस सारी जड़ता के जिम्मेदार विधायकों को हराया है और इस सदन

के अंदर नये विधायकों को निर्वाचित करके शत प्रतिशत इस सदन को नई जिम्मेदारी और नया इतिहास बनाने का मौका दिया है। हमारे दो सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय जो निर्वाचित हैं और कल जो प्रोटेम स्पीकर थे, उनको सदन का सदस्य रहने का मौका मिला, लेकिन उनकी ईमानदारी के कारण एक बार मौका देने के बाद पार्टियों ने दुबारा उन्हें मौका देना उचित नहीं समझा। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिनको वर्तमान राजनैतिक पार्टियों ने नकार दिया था, उपेक्षित कर दिया था, आज आपको क्रान्ति दूत के रूप में भारतीय राजनीति के नये अध्याय को स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी दी है और ये सदन सारे लोग जो पिछले एक डेढ़ साल से इस सदन में सदस्य हैं, उनके कन्धों पर है कि एक नई परम्परा को, एक नये उच्च आदर्शों को और दिल्ली की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिल जुलकर नये विधान भी बनायें और इसको अधिकरिक तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए भी हम कार्य करेंगे। अभी उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखा है।

साथियो, हिन्दुस्तान लम्बे समय तक अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए हिन्दुस्तान में हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना तन-मन-धन लगाकर के इस देश को आजाद कराया, लेकिन 1947 में हिन्दुस्तान के लोगों को जो आजादी मिली, वह अधूरी आजादी थी। हिन्दुस्तान के आवाम को, हिन्दुस्तान के आम आदमी को हिन्दुस्तान की सत्ता के संचालन में कोई हिस्सेदारी का direct प्रावधान नहीं रहा। आज पूरा हिन्दुस्तान दिल्ली विधान सभा के सदस्यों की तरफ, इस सदन की तरफ देख रहा है ओर जैसा अभी उपराज्यपाल महोदय ने भी सरकार की तरफ से संकल्प व्यक्त किया है कि इस विधान सभा को पूर्ण स्वराज के लिए काम करना है और 5 साल में नई सत्ता और जो नई व्यवस्था को

निर्मित करने की जिम्मेदारी भारतीय राजनीति की परम्पराओं को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी को स्वराज कानून को बनाकर स्थापित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, जो हमारे कन्धों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय राजनीति के एक मजबूत और स्थाई, पूर्ण स्वराज की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम के अधूरे लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं। आजादी के बाद से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये स्थितियाँ बन गईं कि जो सरकार का खजाना है, जनता के टैक्स का पैसा है, उस पैसे में से विकास के लिए जो भी मद खर्च होते हैं, उसमें से ४० से ९० प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज इस सदन के सामने यह भी जिम्मेदारी है कि जन लोकपाल कानून जो पिछली बार इस सदन के अंदर इसलिए नहीं प्रस्तुत हो पाया क्योंकि इस सदन में जन लोकपाल के पक्ष में हाथ उठाने वालों की संख्या कम थी। उस कानून को पूर्ण रूप से पारित करने के लिए ही दिल्ली की जनता ने आज प्रचंड बहुमत से दिल्ली में एक सरकार बनाई है। जिससे कि उस मकसद को पूरा किया जा सके और दिल्ली के अंदर एक रोल मॉडल स्थापित किया जा सके जो हिन्दुस्तान के लिए अनुकरणीय बन सके। जिससे कि हिन्दुस्तान के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके और हिन्दुस्तान के अंदर उस दिशा में काम आगे बढ़ सके। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हमारे लिए सबसे प्राथमिक प्रश्न है। क्योंकि यह वह प्रश्न है जो वर्तमान बजट के लूट को रोक देने से विकास की रफ्तार बहुत आगे बढ़ सकती है। लोग सही प्रश्न उठाते हैं कि पैसा कहाँ से आयेगा। पैसे के लिए नये-नये रास्ते सरकार बनायेगी। उसकी चर्चा अभी उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हुई है। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि जो सदन के पास बजट है, जो सरकार के पास बजट है, उसमें जो ४० प्रतिशत लूट हो रही है, उसको रोक दिया जाये तो विकास की रफ्तार उसी प्रतिशत में आगे बढ़ सकती

है। और वह जिम्मेदारी इस सदन को जनलोकपाल की सारी बाधाओं को दूर करते हुए विधान सभा के अंदर उस जनलोकाल कानून को पास करना है और पिछले 4 साल से हिन्दुस्तान जिस लड़ाई को लड़ रहा था, उनके सपनों को भी साकार करना है। ये जिम्मेदारी हम सारे लोगों के कन्धों पर है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सरकार और इस सदन की बहुत ही पवित्र मंशा है, हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। जितना काम करना होगा, करेंगे, सदन के अंदर भी, सरकार भी करेगी। लेकिन दिल्ली के अंदर एक चीज है, जो उस सारे सपने की पूर्ति में एक बाधा के रूप में आ रही है। वह है दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलना। दिल्ली के अंदर जब से सदन के अंदर चर्चा होती रही, चाहे वह कांग्रेस पार्टी रही, चाहे वह पक्ष रहा हो, चाहे वह विपक्ष रहा हो, सभी लोग इस बात से सहमत रहे हैं अब तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी और सरकार ये चाहती है कि दिल्ली के लोग जितनी मजबूती के साथ आज एक नई सरकार के गठन के लिए खड़े हुए हैं, उनकी आकांक्षा है कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दिल्ली वाले अपने विवेक से, अपनी मेहनत से, अपने पैसे से स्वतंत्र होकर दिल्ली की सुरक्षा की भी गारन्टी करना चाहते हैं। और दिल्ली की सुरक्षा की गारन्टी बिना पूर्ण राज्य का दर्जा मिले नहीं हो सकती। आज हम सारे यहां बैठे हैं। विपक्ष में हमारे जो साथी बैठे हैं। पुराने साथी नहीं हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब 2008 में सदन चल रहा था, उस समय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थीं। इसी सदन के अंदर जब उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद प्रतिपक्ष के नेता श्री विजय

कुमार मल्होत्रा जी ने अपनी बात रखी थी, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने बहुत जोर-शोर से सदन में बात उठाई थी कि दिल्ली की सरकार को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ना चाहिए। पूरी मजबूती से आवाज उठानी चाहिए क्योंकि जब तक पुलिस, डी.डी.ए. और संबंधित विभाग दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आएंगे तब तक दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज, उस सरकार ने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज पूरी मुस्तैदी से, पूरी जिम्मेदारी से केन्द्र सरकार से नम्र-निवेदन करती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विपक्ष के साथी बैठे हैं, वो अपने उनके जो पुराने वायदे थे, स्टैंड थे जब अपना वक्तव्य रखेंगे तो उस पर जरूर क्लियर करेंगे कि सरकार की इस पूर्ण राज्य की लड़ाई में वो साथ खड़े हैं या उनका स्टैंड बदल गया है। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि पूरा सदन दिल्ली की सम्पूर्ण जनता की तरफ से केन्द्र सरकार के सामने जैसा पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के निवेदन कर चुके हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसलिए दिया जाए कि आज सदन में सारे लोग निर्वाचित होकर के आये हैं दिल्ली की सारी जनता ने विश्वास करके हमें यहाँ सदन में भेजा है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हमारी बहन के साथ अगर बलात्कार हो जाये, हम चुपचाप यहाँ बैठे देखते रह सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, आज पुलिस की मनमानी चल रही है **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि मंत्री महोदय को बोलने दें।

उप मुख्यमंत्री : मेरा सदस्यों से निवेदन है कि पहले वक्तव्य पूरा **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि मंत्री जी का वक्तव्य पूरा होने दें।

उप मुख्यमंत्री : पहले धन्यवाद प्रस्ताव पूरा होने दें।

अध्यक्ष महोदय : एक बार बैठिये जरा। मैं सदन की भावना को समझता हूँ मैं स्वयं भी, मेरा परिवार भी महिला सुरक्षा से पीड़ित है, मैं समझता हूँ दिल्ली का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार में आज तक कोई चैन स्नैचिंग न हुई हो और बलात्कार की घटनाएँ, गाड़ियों के शीशे ये वो उसके बावजूद भी एक-एक घंटा गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, पकड़े नहीं जाते, यह दिल्ली की बहुत भयानक स्थिति है। मैं इस पर पूरा समय दूँगा। इस विषय पर चर्चा होगी, महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैं मंत्री महोदय जी से प्रार्थना करूँगा अपना वक्तव्य आगे जारी रखें।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सदस्यों ने जो भावनाएँ रखी हैं, पूरी दिल्ली इसी तरह के कराह रही है, लेकिन यह भारतीय राजनीति के अध्याय में दुर्भाग्य है कि एक सदन ऐसा भी है जो जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करता है लेकिन इस राज्य के अंदर पुलिस कुछ भी करे, मनमानी करे, लापरवाही करे लेकिन यह सदन कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मसला पार्टी का नहीं है, यह मसला इस सदन का नहीं है, यह मसला दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा का है, दिल्ली के वो कमजोर लोग जिनसे अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। ई-रिक्शा वाले जिनको रोजगार हमने नहीं दिया, जिनको रोजगार केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, जिन्होंने ई-रिक्शा के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी को चलाने के लिए अपने प्रयास किए, आज आठ महीने से वो दुर्दशा की जिंदगी जी रहे हैं

और आज सरकार बनने के बाद दिल्ली की पुलिस इन्टेंशन के द्वारा उन ई-रिक्शा वालों को, जो घरों में रिक्शा रखते हैं, उसको उठाकर के थाने में बंद कर रही है और कह रही है कि केजरीवाल को बुला लाओ, अब तो तुम्हारा मुख्यमंत्री बन गया, ऐसी जो भावना और दुर्भावना के साथ काम किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर विधायकों को इन्टेंशनली एफ.आई.आर. दर्ज करके उनके मोरेल को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और इस बात का propaganda बनाने की कोशिश की जा रही है और पिछली बार भी की गई थी कि आप धरना नहीं दे सकते, आप बोल नहीं सकते लेकिन हमारे सामने इस सदन को इस मसले का समाधान निकालना है कि अगर हमारे सामने हमारी माँ का बलात्कार होगा, अगर हमारे सामने एक रिक्शे वाले को लाठी मारी जाएगी, अगर एक गरीब को तड़पाया जाएगा तो क्या इस सदन का सदस्य बोलेगा या गूंगा-बहरा बनकर बैठा रहेगा, इस बात का भी फैसला होना है ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप प्लीज बैठिये।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा सदस्यों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि वक्तव्य पूरा होने दें, उसके बाद यह बात रख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बार मंत्री जी का वक्तव्य पूरा होने दें, फिर उसके बाद आपको समय देंगे, इस पर चर्चा करने के लिए, थोड़ा शांति बनाये रखने में सहयोग करें।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद है कि सदन इस पर कोई न कोई निष्कर्ष आगामी दिनों में जरूर पहुँचेगा और कोई फैसला करेगा जिससे कि दिल्ली का यह सदन, दिल्ली की यह चुनी हुई सरकार इस पर एक ठोस

जवाबदेही दिल्ली की जनता को दे सकें और दिल्ली की सरकार कोई ठोस जवाबदेही तभी दे सकती है तब दिल्ली पुलिस को किसी न किसी तरह से इस सदन के प्रति जवाबदेह बनाया जाये तभी दिल्ली के प्रति जवाबदेही को पूरा किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर और भी विकास के लिए तमाम मानचित्र इस सरकार ने बनाये। लेकिन उस विकास के नये मानचित्र को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जमीन भी आज दिल्ली सरकार के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट के पास है, डी. डी.ए. के पास है, अन्य विभागों के पास है, जो सीधे दिल्ली सरकार के हिस्से में नहीं आते हैं। इसलिए दिल्ली के समग्र विकास के लिए भी जरूरी है कि यह पूर्ण राज्य के दर्जे का ऐतिहासिक काम इस सदन के माध्यम से सदन के समस्त सदस्यों के सहयोग के माध्यम से पूरा किया जाए और अगर यह काम होता है तो यकीन मानिये दिल्ली के अंदर इस सरकार ने उपराज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से जो सपना देखा है, दिल्ली का यह सदन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद से जो अधूरे काम रह गए हैं उसके लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा और भारतीय राजनीति में एक नये अध्याय को स्थापित करने का काम करेगा। दिल्ली के अंदर विकास तो हुआ है लेकिन असमान विकास हुआ है। दिल्ली के आप तमाम हिस्से में चले जाइये, एक हिस्से में जाएँगे तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि गाँव से भी बदतर हालत क्यों है और यह भी तो उसी दिल्ली के हिस्से हैं और दूसरे हिस्से में चले जाइये तो आपको पता ही नहीं लगता है कि यह 180 डिग्री का अंतरविरोध क्यों है दिल्ली में, यह सरकार और यह सदन हम इस बात के लिए संकल्पित होना चाहते हैं और रास्ता निकालना चाहते हैं दिल्ली राजधानी में रहने वाले हर क्षेत्र और हर क्षेत्रवासी को विकास का समान अधिकार मिले, जिससे समस्त दिल्ली वालों के बच्चों की

शिक्षा की गारंटी हो, उनके स्वास्थ की गारंटी हो, बेहतर सड़क की गारंटी हो, उनकी सुरक्षा की गारंटी हो और यह समग्र विकास के संकल्प को यह सरकार लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। आज पूरी दिल्ली के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग एक आशा भरी निगाह से इस सरकार की तरफ देख रहे हैं, इस सदन की तरफ देख रहे हैं, मैं यह जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ अब तक प्रतिनिधि जो चुनकर आते थे, उनकी भी जिम्मेदारियाँ थीं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी क्षमता के अनुरूप काम किया है। लेकिन इस सदन में बैठे हुए लोगों के ऊपर जिम्मेदारी पहले से बहुत ज्यादा है। सरकार के ऊपर पहले से जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जिन बातों को आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत के सपनों को जो पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है। हमने सड़क पर जब आन्दोलन किया था, हमने आवाज उठाई थी। जब सरकारों ने बात नहीं मानी, तब हमने कहा था कि इस देश को बदलने के लिए केवल सड़क पर आन्दोलन की जरूरत नहीं है। सदन में भी राजनैतिक क्रान्ति की जरूरत है। जनता ने अपना काम पूरा कर दिया है। हमें अपने काम को पूरा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। आज हमें जनता ने पूरा हक दिया है, पूरी मोहब्बत दी है, पूरा प्यार दिया है और पूरा सम्मान दिया है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस 5 साल की अवधि के दौरान दिल्ली के अंदर आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के जो सपने अधूरे रह गये थे, भ्रष्टाचार ने जो उसके ऊपर काली चादर उढ़ा ली थी। जो हमारे प्रतिनिधियों की निष्क्रियता ने, लापरवाही ने लोगों के मन में गुस्सा पैदा कर दिया था, राजनीति से नफरत पैदा कर दी थी। नेता शब्द से चिढ़ पैदा कर दी थी। इस सदन के ऊपर वह जिम्मेदारी है कि उस नई परम्परा को अपने अन्दर पैदा करो। जैसे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को लोग सम्मान करते हैं, इस सदन के लोगों को लोग सम्मान करने में उनको गर्व महसूस हो कि हमारे ये नेता हैं और सुभाषचन्द्र बोस की परम्परा के नेता

हैं। इस परम्परा को स्थापित करने के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारा व्यवहार, हमारा कर्त्तव्य और हमारी मेहनत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। आज सदन के अंदर अलग-अलग सारे साथियों की जो भावनाएं हैं, जो सोच है, हम सब को मिलकर के एक ताना-बाना बनाना है और जैसा उपराज्यपाल महोदय ने इस सदन में अपनी बात रखी है, उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होना है और सारी ताकत लगाकर एक नये मापदण्ड को स्थापित करना है। धन्यवाद, शुक्रिया, इन्कलाब जिन्दाबाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीन कुमार जी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री प्रवीन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का और दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सरकार में भरोसा जताया और मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बिजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूँगा कि वे प्रस्ताव पर अपने विचार रखें।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ कि उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सिर्फ एक रस्म अदायगी बनाकर यहां पर आज प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे ध्यान में जहां तक है और मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली की विधान सभा का 1993 से अब तक का कार्यकाल रहा हो, या फिर 1967 से 1990 तक दिल्ली महानगर परिषद् का कार्यकाल रहा हो, विधान सभा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर तुरन्त तभी चर्चा को प्रारम्भ किया जा रहा है। परम्पराएं हैं कि उपराज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देते हैं। अर्थात सरकार का कार्यक्रम जनता के बीच में आता है, उस पर चर्चा होती है, उस

पर विचार होता है। और फिर अगले दिन या एक दो दिन बाद सदन की विशेष बैठक बुलाकर उस अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेकिन कल से लगातार परम्पराओं को तार-तार किया जा रहा है और उसी शृंखला में आज भी परम्परा को तार-तार किया गया है। इसका अर्थ साफ है, सरकार के कार्यक्रम में जो ये निहित बात की गई कि पारदर्शिता का तकाजा है सरकार के कार्यकाल में या कार्यक्रम में, उसकी बड़ी भारी कमी साफ रूप से नजर आ रही है। दूसरा मंत्री जी ने ये धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर पेश किया है। थोड़ी देर के लिए तो मैं कन्फ्यूज हो गया कि ये चर्चा उपराज्यपाल के अभिभाषण पर होगी या मंत्री जी के अभिभाषण पर। क्योंकि मुझे ये बात कहने में अफसोस भी हो रहा है और तकलीफ भी कि मंत्री जी के भाषण का, मंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव का सरकार के कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं था। उपराज्यपाल महोदय के वक्तव्य से कोई लेना देना नहीं था। मंत्री जी के भाषण में अधिकारों की ज्यादा बात की जा रही है और जिम्मेदारियों की न के बराबर बात की गयी है। दिल्ली की विधान सभा में इतना संक्षिप्त वक्तव्य जो सिर्फ शब्द जाल से जिसे पूरा करने की कोशिश की गयी है, जिसमें सरकार की इच्छाशक्ति की एक प्रकार से कमी पूरे तौर पर नजर आ रही है। और ये लग गया है कि सरकार दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम करने की स्थिति/मनोस्थिति में नहीं है। सिर्फ अधिकारों की बात करने की बात कर रही है। बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारे ...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप घबराइये नहीं। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप प्लीज बैठिए। आपको बोलने का मौका मिलेगा। अलका जी, त्यागी जी आपको मौका मिलेगा बोलने का। आप चिन्ता न करें, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, बैठिए प्लीज।... मैं रोक रहा हूँ। आप बैठिए। आप बीच में मत बोलिये। मैं रोक रहा हूँ उनको। मेरा पूरा ध्यान है जगदीश जी उधर। आप बैठिए प्लीज।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप निन्दा सुनने की भी आदत डालिए। गलतफहमी से आये हैं सदन में आप। आप ये मत सोचिए कि संख्या बल में आप बहुत अधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप टिप्पणी न करें प्लीज अपना वक्तव्य दीजिए। उससे गर्मी और बढ़ेगी। आप टिप्पणी न कीजिए। अपना वक्तव्य दीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 दिन के कार्यकाल में लगभग सरकार द्वारा बोगस फरमान जारी किए गए। बोगस फरमान। बोगस फरमान। जनता को गुमराह करने के फरमान और ऐसे फरमान सच्चाई से जिनका कोई सरोकर नहीं है। बोगस फरमान। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जनता के सामने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता सब समझने लगी है। जनता के दरबार में....**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मेरा सहयोग करने के लिए आप सब का हृदय से आभार। वे सदन के पुराने सदस्य हैं और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपने सदस्यों को समझायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपना वक्तव्य पूरा करने दें। उसके बाद आपको पूरा समय मिलेगा। आप उनके बिन्दुओं को नोट करें और उसका उत्तर दें।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बोगस फरमान की जब मैंने बात की। तो सरकार ने एक बोगस फरमान जारी किया था कि..

...(व्यवधान)...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : झुग्गी बस्तियों...जब मैं सदन में आया तो मुझे लगा कि सरकार का नया कार्यक्रम सामने आयेगा। बड़ी उत्सुकता थी जानने की। लेकिन जनाब खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। पूरी कर दीजिए न। खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं बोगस फरमानों की बात कर रहा था। पहला बोगस फरमान अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होगी। झुग्गी बस्तियों पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई जारी है। एक भारत की सरकार ने 29 दिसम्बर, 2014 को दिल्ली स्पेशल लॉ 2014 लागू किया था। शायद सरकार की जानकारी में नहीं था। सरकार अनभिज्ञ है। सरकार को अनुभव की कमी साफ रूप से नजर आ रही है हमको। सरकार के अंदर अनुभवहीनता है।

सरकार के अंदर अनुभवहीनता है और इसीलिए यह बोगस फरमान जारी हो रहे हैं। दोस्तो, उसके बाद एक बोगस फरमान और जारी हुआ और वो है **...(व्यवधान)...** ऑरेंज इंडस्ट्रीज में मिडिल और स्मॉल स्केल में डी.पी.सी.सी. के एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं होगी, यह फरमान जारी हुआ, आदेश डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने वो सर्कुलर जारी कर दिया और डी.पी.सी.सी. को विश्वास तक में नहीं लिया, उनकी जानकारी तक में नहीं डाला, उनसे कोई इस पर राय-मशविरा तक नहीं किया। ये एकतरफा बात करते हैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की और दूसरी तरफ झूठे फरमान निकालने हैं लोगों को गुमराह करने की क्योंकि वो भी पूरी तरह बोगस फरमान सिद्ध हुआ, एक भी सेक्रेट्री को, एक भी इंडस्ट्री

को बिना डी.पी.सी.सी. के सर्टीफिकेट के कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। उसके बाद ...**(व्यवधान)**... उसके बाद कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉईज को, जो लोग मेरे पुराने साथी हैं, वो जानते हैं आपकी तरफ भी बैठे हैं बहुत सारे कि हम लोग इन चीजों से रुकने वाले भी नहीं हैं और झुकने वाले भी नहीं हैं। वो जानते हैं इसलिए आप समझ लीजिए ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप अपना वक्तव्य पढ़िये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : यह जो कुछ आप कर रहे हैं, यह मेरे लिए टॉनिक का काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज शांति रखिये। Please keep silnce.

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : दूसरा, एक और बोगस फरमान कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉईज को हटाया नहीं जाएगा, हटाने का तो विषय ही नहीं था, हटाने का विषय कहाँ से आ गया, हटा कर देखे सरकार, एक भी कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को हटाकर देखे सरकार, दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष होगा, सवाल था रेग्युलराइज करने का, आपने कहा था कांट्रेक्चुअल एम्प्लाईज को रेग्युलराइज किया जाएगा, सरकार के इस कार्यक्रम में और सरकार के बोगस फरमानों में कहीं कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉईज को रेग्युलराइज करने का, क्लास IV एम्प्लॉईज को रेग्युलराइज करने का संकल्प इसमें नहीं है ...**(व्यवधान)**... अभी मेरा वक्तव्य जारी है, मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा बुलंद है, क्योंकि मेरी आवाज में सच्चाई है और सच की आवाज हमेशा बुलंद होती है ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, बैठिये। प्रवीण जी, बैठिये। त्यागी जी, प्लीज बैठिये। बिजेन्द्र जी, आप बोलिये। आप अपना वक्तव्य जारी रखिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : सच में हमेशा ताकत होती है, संख्या बल पर दबाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने रामलीला मैदान से घोषणा की थी व्यापारियों के लिए, व्यापारियों को तंग नहीं किया जाएगा, व्यापारियों का सहयोग किया जाएगा, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आज दिल्ली के हर बाजार में व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है .....**(व्यवधान)** आज दिल्ली के व्यापारियों में चर्चा हो रही है, हड़कंप मचा हुआ है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, आप कन्क्लूड कीजिए, दस मिनट हो गये हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अगर आप इस तरह से, फिर वही कल वाली स्थिति आ जाएगी। मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाये। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने दी जा रही है, आप सोच रहे हो कि दस मिनट में यह खत्म हो गया, तो क्या विपक्ष भी दस मिनट में अपनी बात खत्म कर देगा .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, आप बैठिये। बाजपेयी जी, बैठिये। मैं आपको समय दूँगा, आप थोड़ी देर रुकिये। त्यागी जी, दो मिनट रुकिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मुझे लगता है, सत्तारूढ़ दल को अपने अधिकार क्षेत्र में और इस सदन की चारदीवारी के अंदर जो अधिकार प्राप्त है उन पर चर्चा करने के अलावा सब कुछ कहने की वो कोशिश करेंगे। यह बहुत शर्म की बात है, शेम, शेम, शेम।

अध्यक्ष महोदय : बिजेंन्द्र जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ, इस चारदीवारी में लोकतंत्र के इस मंदिर में जो जिम्मेदारी आपकी तय हुई है आप उस पर .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। बिजेन्द्र जी, आप इधर मेरी ओर देखें।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : यहाँ पर टीका-टिप्पणी करके विपक्ष की भूमिका को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप इधर देख कर बात करिये। आप अपना वक्तव्य जारी रखिये। समय निर्धारित है और उसके हिसाब से आपको समय दिया गया है। आप इसको, देखिये, आप मेरी बात सुनिये, प्लीज सुन लीजिए। फिर बाद में दिक्कत होगी। दस मिनट का समय था, दस मिनट का समय पूरा हो चुका, मैं और आपको, मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकेंड बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको दो मिनट का और समय दे रहा हूँ।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : पूरी तो कभी होगी नहीं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : एक सेकेंड। मैं सीमित समय में .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, मेरा यह कहना है इस तरह की बातों में हम जायेंगे तो यह वक्तव्य पूरा दिन भी चलेगा तो पूरा नहीं होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करिये, यह जो आपकी टू द प्वाइंट बातें हैं उनको रखिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : जी, मैं टू द प्वाइंट ही बात कर रहा हूँ, आप सदस्यों को शांत करएं, मेरा आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं मैक्सिमम आपको पाँच मिनट और देता हूँ, दस मिनट दे चुका हूँ। पाँच मिनट में आप कन्क्लूड कर दीजिए। घड़ी सामने मेरे है।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की लेकिन उसके बाद दिल्ली के बाजारों में हड़कंप मच गया, हमको लगा.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में नहीं टोकिये प्लीज, मेरी प्रार्थना है। आप बीच में न टोकिये, उनको बोल लेने दीजिए। जो कुछ वो बोलना चाहते हैं उनको बोल लेने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : हमको लगा यह सब क्या हो रहा है, तो मालूम चला कि मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूँगा बोलने का। आप बैठिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी को अधिग्रहण बिल के धरने पर भी जाना है, इसलिए यह सारी जल्दबाजी की जा रही है। मुझे मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप इन बातों में मत जाइये। आप अपनी बात रखिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अभी उनको भूमि अधिग्रहण बिल के धरने पर जाना है इसलिए जल्दबाजी की जा रही है। रस्म अदायगी हो रही है सदन में, चर्चा नहीं हो रही। रस्म अदायगी हो रही है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड बिजेन्द्र जी। देखिये, मेरी प्रार्थना है अब कोई सदस्य बीच में न बोले। आपको मैं समय दूँगा, उनका तीन-चार मिनट का और समय बाकी है उनको बात कर लेने दीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : स्टॉप वॉच रख लीजिए आप, आधा मिनट भी नहीं हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : चलिये आप बोलिये। मेरे सामने घड़ी है मुझे रखने की जरूरत नहीं है।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मेरे फोन में स्टॉप वॉच है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, मेरे सामने घड़ी है, आप बोलिये। प्लीज, बीच में मत बोलिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : उसके बाद मुझे लगा कि यह हड़कंप क्यों है तो मुझे जानकारी आई कि मुख्यमंत्री जी ने वैट कमिश्नर को, वैट ऑफिसर्स को अपने दफ्तर में बुलाया है और उनको कहा कि मुझे नहीं मालूम मुझको xxxx चाहिए, xxxx, आपने बीस हजार करोड़ इकट्ठा किया है अब तक, मेरे को xxxx चाहिए, कैसे लाओगे मुझे नहीं पता। यानी एक तरफ व्यापारियों को कहा गया आपका सहयोग होगा, आपका harassment नहीं होगा और दूसरी तरफ अधिकारियों के सामने कहा कि हम को नहीं मालूम आप कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, हमको xxxx चाहिए। यह दोहरा मापदण्ड.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी, अल्का जी, उनको बोलने दीजिए। एक सेकेंड, मैं सेक्रेट्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ यह जो आरोप लगा है जो शब्द तीस हजार करोड़ बोले हैं ये आज की कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : कौन सा वाला?

अध्यक्ष महोदय : तीस हजार करोड़ की जो आपने बात कही है। कोई सबूत है आपके पास।

---

xxxx चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी मना कर दें।

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेंड, आप शांति से सुनिये। मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकेंड बाजपेयी जी, बैठिये प्लीज। It is a serious matter now.

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर दें।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, मुख्यमंत्री जी करेंगे।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अगर मुख्यमंत्री जी यह कह दें कि मैंने नहीं कहा तो आप निकाल दें।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार प्लीज। बिना सबूत के सदन में कोई बात रखना.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : सबूत तो सामने बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं होता।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या।

अध्यक्ष महोदय : आपके ऊपर कोई आरोप लगाने लगे।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही से बाहर निकाल दीजिए। आगे जाप जारी रखिये।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप बतायें, अगर मैं गलत हूँ.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैं रख रहा हूँ। आप बोलिये, आप इस तरह की बात करेंगे मैं उनको रोक नहीं सकता। आप उनको उकसायेंगे, मैं उनको रोक नहीं सकता। बड़ा कठिन काम है। आप बैठिये। प्रवीण जी, बैठिये .....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं जो कुछ कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा।...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं सौगन्ध खाता हूँ इस बात की कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा।

...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं सच के ऊपर आधारित...जो कुछ कहूंगा सच के ऊपर आधारित होगा। सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। प्लीज बैठिए। साइलेन्स प्लीज।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, प्लीज बैठिए।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें 10 मिनट से ज्यादा समय मिल चुका है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इनके दस मिनट पूरे हो चुके हैं। इनको बैठने के लिए कहा जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, मैंने 5 मिनट और बढ़ाये हैं।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की आज कार्यवाही है। कार्यवाही पर.....**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : कहाँ। से बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया जारी रखिये।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूँ। आप प्लीज थोड़ा शांति रखिये। आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा। विधिवत तरीके से मिलेगा।

...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी रूलिंग दी थी। मेरे शब्द निकालने की। मेरा उस पर विरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। बिजेन्द्र जी बात सुन लीजिए। ये बात ठीक है कि मैंने रूलिंग दी 5 मिनट की। लेकिन आप हर मुद्दे पर छेड़खानी वाली बात रखेंगे, तो उधर से आवाजें उठेंगी। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। ये सदन है। इस सदन की गरिमा बनाये रखना हम सब का सामूहिक दायित्व है। आप अपनी बात पॉजिटिव वे में रखें। ठीक ढंग से रखें।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दें। नहीं तो रूलिंग वापस लीजिए आप। आप रूलिंग वापस लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप रूलिंग वापस लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : न न मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप रूलिंग वापस लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : वरना मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। अगर वे स्पष्ट करेंगे ...आप आम आदमी पार्टी **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : ये शब्द मैंने निकाल दिए हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप तानाशाही मत करिए। मेरा आपसे अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऊँची आवाज में मत बोलिये। प्लीज। अध्यक्ष के पद की गरिमा बनाए रखें।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैंने कहा मेरी आवाज ऊँची रहेगी। अगर आप दमनकारी तरीका अख्तियार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप तटस्थ रहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कल वाला वातावरण यहां दुबारा पैदा कर रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अगर मुख्यमंत्री कहें कि नहीं कहा है। तो सरैण्डर कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कल वाला वातावरण दुबारा पैदा कर रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं कहा। आप ये बताइये।

अध्यक्ष महोदय : सदन का कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। आप कन्क्लूड अगर करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। त्यागी जी मैं बात कर रहा हूँ न। बैठिए प्लीज। अध्यक्ष अगर बोल रहे हैं तो आप लोगों को शांत रहना चाहिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिये, बिजेन्द्र जी, मैं फिर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि पॉजिटिव वे में आपको जो चर्चा करनी थी... वो समय बीस मिनट हो गए हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : बीस मिनट हो चुके हैं। मेरी बात सुन लीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए आप। देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं। आपने एक रूलिंग दी है। मेरा उस रूलिंग पर आब्जेक्शन है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दे दीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं वही तो कह रहा हूँ, वे प्रत्यक्ष सामने बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वे अपने वक्तव्य में... मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रमाण क्या है?

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने बोला है।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप उनसे पूछ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, उधर इशारा मत कीजिए आप। सदन की गरिमा को बनाकर रखिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए आप।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आपने प्रमाण मांगा है। मैं दावा पेश कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकेण्ड बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ये सीरियस मैटर है। आप थोड़ा शांत रहिए। आप बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। अब शांत हो जायें। अब सब शांति का दान दें प्लीज। Keep quite please....

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आज तो आप 67 हो, कल तो 267 थे यहां।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी आप इधर देखिए। उधर मत देखिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप के सदस्य ही थे वे सब। जो कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप सदस्यों को मुखातिब होकर के मत बोलिये। मुझसे बात कीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप अपना कन्क्लूड करें। प्लीज। नहीं आप कन्क्लूड करें।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्तव्य पूरा करूँगा। आपने कहा प्रमाण दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हाँ।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं प्रमाण पेश कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : दीजिए प्रमाण।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी..

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, मुख्यमंत्री प्रमाण नहीं हैं। आपने बोला। उनका समय आयेगा। समय आयेगा, वे बयान देंगे।

...(व्यवधान)...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आपकी अदालत में मैं गवाह लेकर आया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो बात कही है। आप समय को लंबा खींच रहे हैं। खराब कर रहे हैं समय। आप सदन के समय को खराब कर रहे हैं। मैंने जो बात कही है।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : जिन्होंने कही है, वो इस सदन में मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे बतायेंगे अपने वक्तव्य में।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अगर उन्होंने नहीं कही तो वे खड़े होकर कह दें।

अध्यक्ष महोदय : वे अपने वक्तव्य में बतायेंगे। आपने कह दिया। उनको वक्तव्य देना है वे बतायेंगे।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप रूलिंग मत दीजिए। सब्जेक्ट टु करवाइये। आज सब्जेक्ट टु करवाइये कि अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात से इनकार करेंगे...

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी मेरी बात सुनने का प्रयास करें। बिजेन्द्र जी आप मेरी ओर..

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं सदन में ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होने दूंगा जो सदन के नियमों के विरुद्ध है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। उनको अपने वक्तव्य में क्या देना है, क्या नहीं देना है। वो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आयेगा। आप अपनी बात को कन्क्लूड कर दीजिए। दो मिनट का और समय दे रहा हूँ। इन बिटवीन कोई नहीं बोलेगा।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी आधा मिनट भी मुझे नहीं दिया। मेरा वही सैन्टेन्स पूरा नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं हो पा रहा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप रूलिंग दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप खुद आगे बढ़ रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आप गलत रूलिंग दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब ये देखिए, दो मिनट खराब हो गए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बोल लीजिए। मैं दो मिनट दूंगा। आपने जो बोलना है, बोलिए। आप दो मिनट बोलिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अब बीच में मत बोलिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 30 हजार करोड़ रु. एकत्रित करने का आदेश दिया है। इसके बाद इस भाषण में कहीं महंगाई पर एक शब्द नहीं कहा गया। जब कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम सत्ता में आयेंगे, दिल्ली में महंगाई कम करेंगे। एक शब्द महंगाई के बारे में इस वक्तव्य में नहीं है। 4500 रु. में स्वाइन फ्लू का टेस्ट होगा, ये भी एक प्रकार से जनता पर भारी बोझ डालने की सरकार द्वारा घोषणा की गयी है। आपने कहा था बिजली हाफ, पानी माफ। लेकिन इस भाषण में तो सब कुछ हो गया साफ। इस भाषण में हो गया सब कुछ साफ। कहाँ गया, वो बता दो मुझे आज। सब कुछ हो गया साफ, वो बता दो मुझे आज। कहाँ गया? बिजली हाफ पानी माफ।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, एक मिनट शेष है। आप अपनी बात कन्क्लूड कीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिजली, वाई-फाई के बारे में भी इसमें कोई कमिटमैन्ट नहीं है। दूसरा हमारा कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी सरकार का कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नजर नहीं आया। शिक्षा के मामले में दिल्ली के अंदर डोनेशन्स के नाम पर जिस तरह से शिक्षा का

व्यावसायीकरण हो रहा है। उसमें भी सरकार की कोई इच्छाशक्ति हमें नजर नहीं आई। कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि जब दाखिले हो ही जायेंगे, सब कुछ खत्म ही हो जायेगा, उसके बारे में भी कोई टाइम बाउण्ड इसी सैशन में, सभी अभिभावकों के साथ न्याय होगा, कोई बात नहीं कही गयी। इसके साथ-साथ मैं। आपको दिल्ली की स्लम बस्तियों में जो गरीब लोग रहते हैं, उनको मकान देने के नाम पर भी सरकार कन्नी काट गयी। और अनधिकृत बस्तियों के नाम पर उनको जोड़कर के उस पूरे मामले में भी दिल्ली की जनता को धोखे में रखा गया।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए। बिजेन्द्र जी।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अधिकारों की बात, जिम्मेदारी की बात नहीं है। जो मुद्दे यहां उठाये गये, जिनका इस सदन से कोई सरोकार नहीं था। अधिकांश बातें मंत्री जी से अपने भाषण में वह कहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सदन को ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के लॉ एण्ड ऑडर के लिए, दिल्ली के होने वाले विकास कार्यों के लिए हम कन्धे से कन्धा मिलाकर अपके साथ खड़े हैं। आप बशर्ते इस पर राजनीति मत करना। नहीं तो मेरी हिदायत है आपको ये जनता है न ये बड़ी समझदार है। समझ लो आप। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद बिजेन्द्र जी।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बात पूरी होने दो। मैं आपके अनुसार बात पूरी कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कर तो दी आपने बात पूरी।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं डेढ मिनट में खत्म कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं पूरी हो गई।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप ये करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं खत्म कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी आप विषय से भटक रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : सर मुश्किल से 30-40 सेकेण्ड में बात खत्म हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : 40 सेकेण्ड में?

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : 40-50 सेकेण्ड बस इससे ज्यादा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : चलिए कोई बात नहीं। आप बोलिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैंने जो कहा है इसे गांठ बांध लो। दिल्ली के लोग देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी देखिए आप फिर टींजिंग कर रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अच्छा आगे चलिए। पारदर्शिता... पारदर्शिता, सोशल वेल्फेयर स्कीम्स के बारे में कोई रोड मैप इस सरकार ने यहां नहीं दिया। कोई यहां पर वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कोई रोड मैप नहीं दिया। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं दी। दिल्ली के हॉकर्स के लिए कोई योजना नहीं दी। दिल्ली के रहने वाले जो अति पिछड़े ...**(व्यवधान)**...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : इस पूरे उसमें एक भी शब्द दिल्ली की साढ़े सोलह प्रतिशत आबादी को किसी भी सोशल वेल्फेयर स्कीम से नहीं जोड़ा गया, इस पूरे भाषण में और मैं कहना चाहता हूँ अभी एक ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बिजेंद्र जी, अब हो गया।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैं अंत में एक और हिदायत दे दूँ माननीय सदस्यों को। न्यूटन का नियम जरूर पढ़ा होगा आपने, जितना नीचे मारोगे, उतनी बॉल ऊपर उछलेगी। यह ध्यान कर लेना, यह ध्यान कर लेना न्यूटन के नियम को इसलिए दबाने की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए साहब, आप सदन के नेता हैं। विपक्ष संख्या बल में कम है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। यह ध्यान कर लेना। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसौदिया जी से प्रार्थना करूँगा, कि अपना वक्तव्य रखें।

उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आज माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधान सभा में दिए गए अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और साथ-साथ अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से और सदन की तरफ से दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस छोटे से डॉक्युमेंट में दिल्ली के आने वाले पाँच सालों में दिल्ली का क्या स्वरूप होगा उसका एक विजन डॉक्युमेंट है, एक पूरा विवरण इसमें दिखाई देता है, एक तस्वीर साफ-साफ दिखाई देती है। कोई भी डॉक्युमेंट उसके शब्दों की, उसके पत्रों की सीमा होती है यह डॉक्युमेंट देखने में भले ही छोटा लगें रहा हो लेकिन यह कवि बिहारी के दोहों की तरह है जो देखने में छोटे लगे, लेकिन घाव करें गम्भीर। मुझे पूरी यकीन है इस डॉक्युमेंट में जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़ने के बाद उन लोगों को जरूर घाव लगा होगा जिन्होंने बड़े जतन से इस देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसने महँगाई और भ्रष्टाचार को हमेशा आगे बढ़ाया है। उन लोगों को जरूर घाव लगा होगा इस सतसैया के दोहे को पढ़ने से जिन्होंने शिक्षा वो चाहे स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो उसको प्राइवेट हाथों में सौंप-सौंप कर इस देश के भविष्य को बर्बाद किया है, इस देश के आम आदमी को लुटने पर मजबूर किया है। मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों को इससे घाव जरूर लगा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इससे उन लोगों को भी घाव लगा होगा जिन्होंने दिल्ली में अनअथोराइज कालोनीज को दुधारू गाय बनाकर रखा हुआ है पिछले कई दशकों से। उन लोगों को जरूर घाव लगा होगा जिन लोगों ने दिल्ली में जब कोई व्यक्ति मकान बनाने चलता है तो उसको देखकर उनको खुशी होती है, खुशी इसलिए नहीं होती कि कोई आबाद हो रहा है, बल्कि खुशी इसलिए होती है कि चलो पर लैंटर एक लाख रुपये का ग्राहक और मिलने वाला है, उन लोगों को जरूर घाव लगा होगा।

मैं उपराज्यपाल महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस डॉक्युमेंट के माध्यम से, इस अभिभाषण के माध्यम से उन लोगों को पीड़ा पहुँचाने के लिए कुछ ऐसी बातें कहीं, इस विजन में ऐसी बातें रखीं कि उनको एहसास हो गया होगा कि अगले पाँच साल दिल्ली के लोगों ने जिस तरह की सरकार, जिस तरह की व्यवस्था की परिकल्पना की है वो साकार होने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और इस सदन के माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक निर्णय देने के लिए इस चुनाव में, यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह सिर्फ कुछ पार्टियों के बीच चुनाव नहीं हुआ था, यह चुनाव अंधा-धुंध पैसे खर्च करके चुनाव लड़ने वाली एक राजनीति बनाम खुलेआम चंदा माँग कर पाई-पाई का हिसाब रखने वाली एक राजनीति के बीच चुनाव था और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि बाकायदा उसने एक सादगीपूर्ण राजनीति, ईमानदारी की राजनीति को चुनकर और चुनकर ही नहीं, सिर्फ बहुमत देकर ही नहीं, बल्कि महा बहुमत देकर यहाँ विधान सभा में भेजा है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को इस सदन के माध्यम से। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा यह बहुमत नहीं महा बहुमत है और इस महा बहुमत के साथ-साथ जिम्मेदारियाँ नहीं, महा जिम्मेदारियाँ इस सदन के ऊपर आई हैं। हमें इसका एहसास है, हमें इस बात का एहसास है कि इस मेनडेट का मतलब क्या है, इस मेनडेट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि 36 विधायक या 40 विधायक दे दिये हैं जाओ जाकर सरकार चलाओ, जाओ जाकर कुछ फाइलें रुकी पड़ी हैं उनको आगे बढ़ाओ, जाओ जाकर फाइल नोटिंग्स में लिखो कि यह होना है यह नहीं होना है, यह करना है यह नहीं करना है कुछ फाइलों की एग्री करो, कुछ को डिस-एग्री करो, कुछ को रोक दो, कुछ को आगे बढ़ाओ,

सिर्फ इतने के लिए नहीं है यह मेनडेट। यह मेनडेट एक बहुत बड़े सिस्मैटिक चेंज के लिए है, बहुत बड़े सिस्मैटिक चेंज की डिमांड प्रस्तुत करता है यह मेनडेट और इस अभिभाषण में उस सिस्मैटिक चेंज का खूब खुलासा बहुत अच्छे से उपराज्यपाल महोदय ने खुलासा किया है। यह मेनडेट इसलिए है सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार चलाने के तौर-तरीके बदलने के लिए एक बड़ा मेनडेट दिया है दिल्ली की जनता ने। क्योंकि हम हमेशा देखते रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम हुआ, लेकिन उसमें कहीं सीमा थी, उस लोकतंत्र में एक सीमा आई कि पाँच साल में अपना राजा चुनिये और अगले पांच साल अपने ही चुने गये राजा के सामने गिड़गिड़ाते रहिये। माई-बाप मेरे सीवर जाम हो गये हैं ठीक करवा दीजिए, माई-बाप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, एडमिशन करवा दीजिए, माई-बाप मेरा बच्चा बड़ा हो गया, उसको कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए आप फोन कर देंगे तो हो जाएगा, माई-बाप मेरे घर नगर निगम वालों ने रैड कर दी है पैसे माँग रहे हैं बचा लीजिए। ये सारी चीजें हैं पाँच साल में अपना राजा चुनना और अगले पाँच साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहना इतने भर को हम लोकतंत्र मानकर बैठ गये थे। चुनाव बहुत अहम हिस्सा है लेकिन चुनाव के बाद क्या, चुनाव के बाद चुने हुए लोगों को क्या करना चाहिए उस दिशा में एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली की जनता ने देना चाहा है और हमें इसका पूरा एहसास है कि सिर्फ कुछ फाइलों को अगले पाँच साल आगे बढ़ाने के लिए अगर हम जुट गये और सिर्फ उस तक सीमित रह गये तो यह आदेश, यह निर्देश जो दिल्ली की जनता का मिला है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें अगले पाँच सालों के संकेत के रूप में भी देखने को हमको मिलती है। बहुत बड़े सिस्मैटिक चेंज की ओर एक इशारा किया गया है इस अभिभाषण में। मैं सदन को और सदन के माध्यम से दिल्ली

की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर, हम सब की प्राथमिकता एक ऐसा सिस्टम रहेगा जहाँ लोगों को नेताओं के पीछे भागने की जरूरत न पड़े। लोगों को छोटी-छोटी चीजों के लिए अपनी आम जिंदगी की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए नेताओं के सामने, अधिकारियों के सामने उनके आगे-पीछे भागने की जरूरत न पड़े, बल्कि सिस्टम खुद-ब-खुद उसको करता रहे और सिस्टम में वो चीजें होती रहें, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए मसले हों या रोजगार से जुड़े हुए मसले हों, व्यापार से जुड़े हुए मसले हों, उन तमाम मसलों पर सिस्टम खुद-ब-खुद अपना काम करता रहे और लोग बहुत भरोसे के साथ अपनी जिंदगी, अपना व्यापार, अपनी नौकरी चलाते रहें और सोचते रहें कि हम सिस्टम के प्रति आश्वस्त हैं सिस्टम अपना काम जहाँ है वहाँ ठीक से कर रहा होगा। वैसा सिस्टम अगर हम नहीं ला पाये, वैसा सिस्टम अगर हम नहीं दे पाये, तो फिर हमारा यह मेनडेट बेकार है। हम उसके लिए भरोसा दिलाना चाहते हैं।

हर दिल्ली वाला चाहे वो बुजुर्ग हो, हर दिल्ली का नागरिक चाहे वो व्यापारी हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति यह कह सके कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ में अपना काम कर रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ और सरकार अपना काम कर रही है, सिस्टम अपना काम कर रहा है और वास्तव में कर रहा है, ऐसी व्यवस्था की ओर अगर हम ले जा सकें, तब हम इसे सफल मानेंगे।

यहाँ इस सदन में बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। उनमें से एक तस्वीर आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी है। बापू ने कहा था कि इस देश की ताकत, इस देश का सिस्टम सत्ता में बैठ हुए बीस लोगों से नहीं चलेगा। इसका सिस्टम तो उनके शब्द अलग थे, उन्होंने कहा था कि इस देश का सारा

सिस्टम केन्द्र में बैठे हुए 20 लोग नहीं चला सकते। मैं इसे देश के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। मैं उसी को थोड़ा संशोधित करते हुए, बस आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि इस देश का सिस्टम, इस दिल्ली का सिस्टम यहाँ बैठे हुए 70 लोगों से नहीं चलेगा। न सात मंत्रियों से चलेगा और न 70 महानुभावों से चलेगा। (तालियाँ) दिल्ली का सिस्टम अगले 5 साल दिल्ली के सवा करोड़ नागरिकों से चलेगा। वो क्या चाहते हैं, वे कैसे चाहते हैं, वे कैसे स्कूल चाहते हैं, कैसी गलियाँ चाहते हैं। सब कुछ उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी निगरानी में चलेगा। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ यहाँ से। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मुल्क में बहुत अच्छे राजनेता हुए हैं। बहुत बड़े-बड़े संत हुए हैं। हम चाहते हैं कि यह देश उस तरफ बढ़े, जहाँ इस देश के लोगों को, देश की व्यवस्था को देखकर लोग बहुत शान से कह सकें, फख्र से महसूस कर सकें कि इस देश में कभी गांधी हुए थे, इस देश में कभी बुद्ध हुए थे। इस देश में कभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेको संत हुए थे। इसी देश में मदर टेरेसा जैसी संत ने अपनी कर्मभूमि बनाया था। लोग फख्र के साथ इन चीजों को महसूस कर सकें। कह सकें। सत्ता उसमें बीच में कहीं टाँग न अड़ाये। अपने भ्रष्टाचार का लालन-पालन करने के लिए अपनी कोठियाँ, अपने महल-दो महले बनाने के लिए नेता और नेताओं के साथ चल रही व्यवस्था उसमें टांग न अड़ाये। ऐसी व्यवस्था हम कायम करना चाहते हैं।

हम ऐसी व्यवस्था सरकार के माध्यम से भी रखेंगे, शिक्षा के माध्यम से भी रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यह सदन एक नई गरिमा, एक नये तौर तरीके से काम करते हुए भले ही उसके लिए कुछ नियम/कायदे-कानूनों को बदलना पड़े, भले ही इसके लिए कुछ परम्पराओं को छोड़ना/तोड़ना/जोड़ना पड़े लेकिन उस तरफ हम लेकर चलेंगे, जहाँ हर व्यक्ति फख्र के साथ कह सके कि यह देश

गांधी का देश है। ये बुद्ध का देश है, ये मदर टेरेसा का देश है। ये सुभाष चन्द्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये लाला लाजपत राय का देश है। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि व्यवस्थागत परिवर्तन बहुत सारे करने होंगे, साथ-साथ फौरी तौर पर व्यवस्था को जिम्मेदार भी बनाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा, वह हम करेंगे।

जब हम बात करते हैं तो लोग पूछते हैं कि साहब, इसके लिए पैसा कहाँ से आयेगा। बहुत बार ये पूछा गया और अभी भी पूछा जाता है कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आयेगा। मैं राजनीति में आने से पहले पत्रकार रहा। पत्रकार होने के नाते भी कुछ चीजों को सोचने समझने का मौका मिला है। राजनीति में आने के बाद 49 दिन इसी सदन के माध्यम से इसी सदन के आदेश से सरकार चलाने का अनुभव भी मिला, अवसर मिला और पिछले कुछ दस एक दिन से और फिर से सरकार के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं बहुत खुले दिन से एक बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार के पास न तो पैसे की कमी होती है और न टैलेण्ट की कमी होती है, सिर्फ नीयत की कमी होती है। उस नीयत पर भरोसा करके इस बार दिल्ली की जनता ने हमें यहाँ भेजा है और हम पूरे भरोसे के साथ कहना चाहते हैं कि उस नीयत पर, उस भरोसे पर, उस उम्मीद पर खरा साबित उतरेंगे। जो चीजें उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही हैं, उनको एक-एक करके और एक साथ आगे बढ़ाने के लिए हम तन मन धन एक करके लगेंगे। सिर्फ संकेत के लिए मैं कहना चाहता हूं। बार बार जब पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आयेगा। तो साहब जब करप्शन रुकेगा तो पैसा भी बच जायेगा। आज करीब 40 हजार करोड़ का बजट है 35 हजार करोड़ का बजट है। कोई सांइंटिफिक आंकड़ा नहीं है इसका। कोई कहता है, 85 परसेंट, कोई 70 परसेंट कोई 50

परसेंट। लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन में जा रहा है। मैं जानता हूँ कि दिल्ली में, बजट के आंकड़े मैंने देखें हैं। नगर निगम और पी.डब्ल्यू.डी. और इस सब को मिला दें और तमाम डिपार्टमैन्टस को, 5 हजार करोड़ रुपये तो दिल्ली में सड़क बनाने पर खर्च होते हैं। 5 हजार करोड़ रुपये तो बहुत होते हैं। 5 हजार करोड़ रुपये में एक नया शहर बनाया जा सकता है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाये, तो मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारा पैसा बचेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से पैसा बचेगा। बहुत सारी फिजूलखर्चियां हो रही हैं, बहुत सारे डिपार्टमैन्ट ऐसे बने हुए हैं, जिनमें अगर 30 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं तो 5 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है। पिछले 5 साल में, 7 साल में ऐसे डिपार्टमैन्टस को रिव्यू करके उन होने वाली फिजूल खर्ची और तमाम योजनाएं, मैं घूमता हूँ दिल्ली की गली गली में घूमता हूं। वहा देखता हूं। जिन पार्क्स में जिन मोहल्लों में सीवर नहीं है, पीने के लिए पाइप लाइन नहीं है, वहां के पार्क में 50-50, 60-60 लाख रुपये में नगर निगम और पिछली सरकारों ने म्युजिकल फाउण्टेन बनवाये हैं। 60 लाख रुपये में म्युजिकल फाउण्टेल जहाँ बना रहे हैं, वहाँ 60 हजार रूपये में मेन होल ठीक करने का पैसा नहीं आ रहा है। ये फिजूल खर्चियां रोककर पैसा आयेगा। ये भ्रष्टाचार रोककर पैसा आयेगा और सबसे बड़ी चीज जहाँ से पैसा आयेगा कि अगर राजनीति के प्रति, व्यवस्था के प्रति देश के लोग, दिल्ली के लोग भरोसा करेंगे तो टैक्स देने से भी नहीं चूकेंगे, पैसा देने से भी नहीं चूकेंगे। भरोसा होने की जरूरत है, भरोसा दिलाने की जरूरत है दिल्ली के लोगों को, कि आप एक पैसा दीजिए। हम उसे सवा पैसा करके लगायेंगे। उसका सवाया वसूल करके दिखायेंगे। आज दिल्ली के लोगों को लगने लगा है कि टैक्स दें तो किस लिए दें? नेताजी के महल में लाल पत्थर लगवाने के लिए? साहबों के बेटों को विदेशों में पढ़ाने के लिए दें।

किस लिए दें? उस भरोसे को हम कायम करना चाहते हैं। उस भरोसे को कायम करेंगे। और जिस दिन वह भरोसा कायम होगा। हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग खुले दिल से दिल्ली की व्यवस्था को अपने लिए खड़ा करने के लिए और ज्यादा पैसा देंगे। जो लोग अभी तक टैक्स नहीं दे रहे थे किसी भी कारण से, वे लोग टैक्स देंगे। मुझे पूरा भरोसा है। और किसी को परेशान करने से नहीं, इन्स्पेक्टर राज से नहीं बल्कि गले लगाने से पैसा आयेगा। जिस जिस को हम गले लगायेंगे, भरोसे के साथ गले लगायेंगे, मुझे यकीन है कि वे दिल्ली को चलाने के लिए तन-मन-धन से खुद को अर्पित करेगा। इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ एक और चीज की जरूरत है और जो इस अभिभाषण में कहीं न कहीं दिखती है। वह है कि हमें...जैसा मैंने कहा कि हमें कुछ परम्पराओं को छोड़ना/तोड़ना/जोड़ना/भी पड़ेगा। कुछ नियम कायदे कानून अगर सरकार पर, व्यवस्था पर और लोगों की जिन्दगी पर बोझ बन गये हैं तो उनको हटाकर कुछ जिन्दगी के लिए जरूरी कानूनों को बनाना पड़ेगा। हमें इस सदन में बैठकर सोचना पड़ेगा कि नियम, कायदे, कानून और परम्पराएं लोगों की जिन्दगी के लिए हैं, लोगों की जिन्दगी नियम, कायदे कानून और परम्पराओं के लिए नहीं है। इस सदन के बाहर जितने लोग बैठे हैं उम्मीद लगाकर। यहां से जो परम्परा निकले, यहां से जो भी कानून निकले, यहां से जो भी नियम बनकर निकले। वह लोगों की जिन्दगी के लिए निकले। लोगों की जिन्दगियाँ यहां से निकले हुए कानून और यहां से निकली हुई परम्पराओं पर हवन होने के लिए नहीं है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे, हम कानून, परम्पराओं से ऊपर उठकर out of the box तरीके से सोचने की आदत डाल लेंगे। और मुझे लगता है कि 5 साल में ऐसी बहुत सारी चीजें नई होंगी, ऐसी बहुत सारी इस दिल्ली बल्कि दिल्ली और मैं कहूं कि दुनिया ने दिल्ली के लोगों का चुनाव करने का

तरीका देखा है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव करने का, ऐसा चयन करने का किसी पार्टी पर ऐसा भरोसा करने का कोई ऐसा प्रेसीडेन्स देखने में नहीं आया। मैं आज भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगले 5 साल इस सदन में बहुत कुछ ऐसा होगा, इस सरकार से बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना अच्छा होगा, ऐसा होगा।

आखिर में, एक बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं कल यहां जब आया, पिछले साल 14 फरवरी, 2014 को हम लोग यहां से गए थे। बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थीं, उन विषम परिस्थितियों में थोड़ा दुखी मन से यहां से गए थे। दुखी इसलिए नहीं कि सरकार छोड़ रहे थे। बल्कि दुखी इसलिए कि इस सदन में जो कुछ देखा और 49 दिन जो देखा और जो महसूस किया उससे बहुत दुख हुआ कि लोकतंत्र का मंदिर ऐसे चलता है। मैं कल जब यहां आया तो बहुत सुखद अहसास हुआ और भरोसा जगा कि कम से कम इस बार इस सदन में कोई माइक टूटने की परम्परा नहीं पड़ेगी। मुझे भरोसा हुआ कि इस सदन का एक-एक मिनट अब उन लोगों के लिए समर्पित होगा, जो बाहर बहुत उम्मीद से बैठे हैं। मैं यहां बैठे हुए अपने तमाम साथियों से पक्ष और विपक्ष से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 2 घण्टे से देख रहा था...एक घण्टे से करीब समय जाया न करे। यह समय अब हमारा नहीं है। ये समय किसी एक सदस्य का नहीं है। ये समय सिर्फ सदन का नहीं है। ये समय अब दिल्ली की जनता का है। अगर हम शोरगुल मचाकर, शोर मचाकर, एक दूसरे की बातों में व्यवधान डालकर किसी का समय बर्बाद करेंगे। हम गैर जरूरी बातें करके, गैर जरूरी मुद्दे उठाकर क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमें प्रिय हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उससे हमारी राजनीति फलती, फूलती है। तो मुझे लगता है कि हम दिल्ली की जनता के साथ अपराध करेंगे। मेरा सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों से अनुरोध है कि इस एक एक मिनट की एक

एक पल की कीमत को समझें। यहां उन्हीं मुद्दों को उठायें जो दिल्ली की जनता के लिए जरूरी हैं। और अब दिल्ली की जनता के लिए जरूरी मुद्दे उठाये जा रहे हों। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ अपनी एकजुटता के लिए व्यवधान भी न डालें। मैं ऐसी उम्मीद पूरे सदन से करूँगा कि अगले 5 साल में हमको कम से कम इस सदन से कुर्सियां फेंकने, माइक तोड़ने, एक दूसरे की बातों में निर्थक व्यवधान डालने और बेकार की बातें करने और बेकार की बातों में जनता का समय जाया करने का ये मौका यहां देखने को नहीं मिलेगा। इस उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ कि हम अपने हिन्दुस्तान को, अपनी दिल्ली को फिर से सजायेंगे, संवारेंगे, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : मनीष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास बहुत कम है। मैं कुछ सदस्यों के नाम बोल रहा हूँ। वे बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। श्री कपिल मिश्रा जी।

अध्यक्ष महोदय : कपिल मिश्रा जी।

श्री कपिल मिश्रा : आरदणीय अध्यक्ष महोदय, 18 सितम्बर, 2007 को ऐसे ही विधान सभा लगी हुई थी और मैं वहाँ खड़ा था दर्शक दीर्घा में, तब कॉमवैल्थ घोटाले की शुरुआत हुई थी और बड़ा उत्तेजित था। अरविंद जी, मनीष जी के साथ हम लोग उसके खिलाफ काम कर रहे थे, कॉमनवैल्थ घोटाले के खिलाफ, खेलगाँव बना रहे थे, यमुना नदी के अंदर उसके खिलाफ और तब वहाँ से मैंने विरोध दर्ज कराया था तब मार्शल मुझे उठाकर ले गये थे इस विधान सभा से बाहर और कल जब इसी विधान सभा में एक सदस्य के तौर पर शपथ ली तब मुझे समझ में आ गया कि अब दिल्ली बदल चुकी है। अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों की आवाज को रोका जाता

था जो लोग दूर से ही चिल्लाते थे, आंदोलन करने पर मजबूर होते थे, अब जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हम लोग यहाँ खड़े होकर उन गलत फैसलों को बदल सकते हैं और सही फैसले कर सकते हैं। यह जो अभिभाषण आया है इसमें जनलोकपाल, स्वराज और बाकी सभी वादों पर जो भरोसा जताया गया है मुझे लगता है कि शायद बिल्कुल सही माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अब एक ऐतिहासिक अगले पाँच साल होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जिसके प्रति आज भी बहुत गुस्सा है और जरूर मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति सदन में 67 विधायक बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के और मुझे पूरा भरोसा है भाजपा के भी जो बाकी तीन लोग हैं आपके पास साहब ऐतिहासिक बहुमत है केन्द्र में और दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक तो यहाँ भी दिया है आपको, यहाँ भी ऐतिहासिक ही है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, एक काम ऐसा है जो शायद हम 67 लोगों के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो लड़ कर लें लेकिन आप तीन कर सकते हैं साहब। आप जाइये, जरा बताइये गृह मंत्री महोदय को देश के उन लोगों को जो दिल्ली पुलिस को संभालते हैं, उनको बताइये, 31 परसेंट बढ़े हैं बलात्कार के अपराध, किडनैपिंग 32 परसेंट बढ़ी है, 18 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं इस दिल्ली शहर के अंदर, चलती हुई गाड़ी के अंदर महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही, वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हर रेड लाइट के थोड़ा आगे बैरियर लगाते हैं और पैसे की वसूली करते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या कर रहे थे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाया जाये, समन किया जाये, उन पुलिस वालों को पूरी सड़क पर जहाँ-जहाँ वो गाड़ी चलती रही थी, जिस-जिस थाने के अंदर वो सड़क आती है जिस-जिस ट्रैफिक पुलिस वाले

की वहाँ जिम्मेदारी लगती थी सब को एक बार बुला लिया जाये, सब की जाँच की जाये वो उस वक्त ड्यूटी के दौरान क्या कर रहे थे। दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं देखी जा रही है। मैं करावल नगर विधान सभा से आता हूँ, सोनिया विहार थाना, करावल नगर थाना, खजूरी थाना, बच्चों के गायब होने की शिकायतें दर्ज होती हैं रोज। संजीव भाई मेरे साथ हैं दो बच्चों के किडनैप होने की घटना पर क्या हुआ वहाँ पर, मुझे यह लगता है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। दिल्ली पुलिस कब हमारे पास आयेगी कब क्या होगा यह बाद की बात है लेकिन यह सदन मूक होकर दिल्ली की कानून और व्यवस्था को बर्बाद होने नहीं देखेगा, नहीं देखने देंगे हम किसी को यह चीज। मुझे यह लगता है.....**(व्यवधान)**

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : पहले जो काम आपके जिम्मे हैं, उनके बारे में बता दो।

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, फिर वही बात आप कर रहे हैं।

श्री कपिल मिश्रा : गुप्ता जी, राजनीति मत कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे थे, वो उपराज्यपाल के अभिभाषण पर दिल्ली की सुरक्षा...**(व्यवधान)**

श्री कपिल मिश्रा : राजनीति मत कीजिये। मैं यह कहना चाहता हूँ अपनी बात खत्म करने से पहले ...**(व्यवधान)** मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ मेरी बात सुनियेगा गुप्ता जी।

अध्यक्ष महोदय : अब आप मुझसे बात कीजिये।

श्री कपिल मिश्रा : एक मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा-

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।

यह विधान सभा मूक होकर नहीं देखेगी। हमारे हाथ में कब ताकत आयेगी, कब नहीं आयेगी यह बाद की बात है, हम मूक होकर नहीं देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक आपके सामने विनती कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इस विधान सभा के अंदर समन किया जाये, समन किया जाये, समन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी बैठिये। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहन अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लांबा : जयहिंद, मैं सदन का तहेदिल से धन्यवाद करती हूँ और अपनी बात को शुरू करने से पहले, मैं वही कहूँगी आज गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में जो महिलाओं की सुरक्षा Fast Track Court के गठन की बात कही, उनके लिए जिस तरह से Home Guards, Civil Defence volunteers की बात उन्होंने कही, बहुत सी बातों को लेकिन मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले तमाम देश के, हमारी दिल्ली की खास तौर से माँ, बहन, बेटियों के लिए दो शब्द समर्पित करके उन्हें हिम्मत देते हुए यह विश्वास दिलाते हुए कि यह सदन में पिछली बार तीन और इस बार दुगुनी छह आपकी बहनें ही नहीं, ये भाई भी हैं कपिल मिश्रा को जब मैं सुन रही थी मुझे खुशी हुई कि इस बार सिर्फ बहनें ही नहीं, ये भाई भी हैं कपिल मिश्रा को जब मैं सुन रही थी मुझे खुशी हुई कि इस बार सिर्फ बहनें ही नहीं, भाई भी देश की तमाम माँ, बहन, बेटियों को सुरक्षा देने के लिए गम्भीर हैं। मैं महिलाओं को दो शब्द कह कर अपनी बात रखूँगी कि -

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है
जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है,
मौत भी तुझसे हारी है

मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस की बात होती है गुप्ता जी फिर खड़े हो जायेंगे बोलने के लिए मुझे मालूम है, जब मैं बात करूँगी कि दिल्ली का लॉ एंड आर्डर, दिल्ली की कानून, पुलिस व्यवस्था, दिल्ली के सदन के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। वो अभी भी नहीं है। कपिल जी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को समन करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करती हूँ बिल्कुल दिल्ली के कमिश्नर को इस सदन के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। आपने कहा निर्भया कांड हुए दो वर्ष से अधिक हो गये हैं, आपने कहा उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगी कि जिन भी इलाकों में इस तरह के अपराध घटित होते हैं वहाँ की पुलिस की सिर्फ जवाबदेही ही नहीं, अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अपराध के बाद उन्हें सस्पेंड भी करके एक नये ईमानदार पुलिस की नियुक्ति वहां पर होनी चाहिए ताकि दोबारा से इस तरह के अपराधों को दोहराया न जा सके। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो दिल्ली में ही, मैं फिर वो कहूँगी, बारी से दोहराऊँगी, बहुत उम्मीदें थीं, एक-एक वोट दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीदों से हमें देकर इस सदन में भेजा है। हमारी जवाबदेही उस एक-एक वोट के प्रति है। केन्द्र सरकार भी बहुत खोखले नारे लेकर आई, दिल्ली केन्द्र शासित राज्य है, इसलिए केन्द्र की तरफ हम उम्मीद से देखते रहते हैं। तीन बी.जे.पी. के सदस्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। केन्द्र में विपक्ष नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इसकी तरफ इन्होंने देखा और घबरा गये कि अब दिल्ली में क्या होगा, क्या हमें विपक्ष की उपाधि दी जायेगी, क्या हमें विपक्ष का दर्जा दिया जायेगा, यह अरविंद जी और इस सदन का बड़प्पन है कि उन्होंने

शायद उसके लिए आपको कंसीडर किया है कि आपकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे। पर हम उम्मीद करते हैं कि आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक मजबूत कड़ी का काम करेंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे की हमारी मांग का हम भरपूर समर्थन करते हैं और मुझे लगता है कि वो चेहरा बनकर आप हमें जब-जब समय हो, आप इस आवाज को देश की पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री तक पहुँचायेंगे ताकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके।

महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो, क्योंकि फुटबॉल की तरह महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली और केन्द्र के बीच में उलझी रहती है कभी बॉर्डर को बताया जाता है कि यह हमारी सीमा से बाहर है, कभी कहा जाता है यह दिल्ली से बाहर केन्द्र का मुद्दा है। 35 प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें बढ़ोतरी हुई है उसके आंकड़े हमें नहीं बताना, गृह मंत्रालय की जो अपनी खुद की वेबसाइट है National Crime Records Bureau वो खुलासा करती है कि दिल्ली में 35 प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं वो बढ़े हैं। अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं कि वो जो नारा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी सरकार को आये आठ महीने हो गये और यह आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल हमारे यहां पर 2444 अगर molestation के केस हुए तो इस बार अभी तक 3450 जो है केस हुए हैं Eve-teasing पिछली बार 790 थे तो इस बार 1024 है, घरेलू हिंसा की अगर मैं बात करूं, जहां पर बहुत सी हिंसाएं आज भी हमारे कानून 2005 में घरेलू हिंसा कानून आया लेकिन उसका क्या हश्र है, हमारे सामने है कि 2370 domestic violence के केस थे और अभी तक 2400 केस दर्ज हो चुके हैं। किडनैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो भी पिछले साल 2050 के करीब थे तो इस बार 2500 का आँकड़ा अभी से पार

कर चुके हैं। दहेज हत्याओं की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 123 दहेज हत्यायें हुई थीं और इस बार अभी 131 दहेज में हमारी बहू, बेटियाँ जल गई हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगी और इन्हीं का आंकड़ा National Crime Records Bureau बताते हैं कि दिल्ली को अभी भी क्राइम कैपिटल का जो दर्जा है, Rape Capital of Delhi जो कहा गया निर्भया के बाद से वो अभी भी कायम है। इस सदन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली भारत की राजधानी है इस पर जो धब्बा लगा हुआ है Rape Capital of India के नाम से, सदन पूरा मिलकर इस धब्बे को धोने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ताकि हम इससे महिला Friendly Capital of India के नाम से बना सकें ताकि देश ही नहीं दिल्ली देश की महिलाएं आकर यहां पर अपने अपको सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं एक बात आपसे और कहूँगी दिल्ली पुलिस के बारे में। यह बहुत अपनी पीठ थपथपा रही है यह कहती है कि दिल्ली में अपराध बढ़े नहीं हैं। हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन, एफ.आई.आर. जो है वो होने लग गई है। मैं इस बात से कतई भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ दिल्ली पुलिस का मानना है कि मान लीजिए अगर 10 केस होते थे पीछे, अभी भी 10 ही होते हैं लेकिन पिछली बार दस में से उनका कहना है पाँच केस दर्ज होते थे इस बार दस में से आठ होते हैं। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं मानती हूं कि अगर मान लीजिए कि दस केस होते हैं। तो इस बार 10 नहीं दुगुने अपराध हुए हैं। ये 35 प्रतिशत का आंकड़ा बताता है। तो पुलिस मुझे लगता है कि इन फर्जी, इन झूठे आंकड़ों से जमीनी हकीकत को जाने और बिल्कुल इस सदन की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में महिलाओं को एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षित भावना से जो फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन होना है, जो नए जजों की नियुक्तियाँ होनी हैं, जो नये कोर्टों का गठन होना है। फिर एक बार दोहराऊँगी अपने बी. जे.पी. के तीन हमारे सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं दिल्ली

को। जितनी उम्मीदें यहां से हैं, उससे दुगुनी उम्मीदें आपसे हैं। इसलिए हैं कि केन्द्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली केन्द्र शासित राज्य है। हर छोटी से बड़ी, दिल्ली का लॉ एण्ड ऑर्डर हो, जमीन हो, कानून व्यवस्था हो, पुलिस हो। आपकी तरफ हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ आरोप लगाने की बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और सदन को ताकत देंगे, जयहिंद।

अध्यक्ष्य महोदय : श्री संजीव झा।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उपराज्यपाल महोदय ने जो विकास का ब्लू प्रिंट रखा है, उससे हम दिल्ली को ऊँचाई पर ले जायेंगे, जहाँ दिल्ली का अंतिम व्यक्ति भी विकास की अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी बात हो रही थी पुलिसिंग की, लॉ एण्ड ऑर्डर की। आज दिल्ली की जनता में इतना गुस्सा क्यों है? एन.सी.आर.बी. की एक रिपोर्ट है 2014 का – दिल्ली देश का सबसे most violent सबसे हिंसक जगह है। ये क्यों है? आज से चार दिन पहले हमने इसकी थोड़ी सी करतूत देखी। उसकी उदासीनता और उसकी बरबरता देखी। मैं बुराड़ी विधान सभा से निर्वाचित होकर आया हूं। आज से 4 दिन पहले शाम को एक अपहरण की घटना होती है। मुझे फोन आता हूं। मैं पुलिस से बात करता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करो। वह आश्वासन भी देता है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दो घण्टे बाद फिर फोन आता है कि जो लोग सौ नम्बर पर पहले कॉल

किया गया था, पुलिस नहीं आई। वहां कालोनी के लोग खुद इनिशिएटिव लेकर बच्चों को recover कर लिया और accused को भी पकड़ा गया। लेकिन जब एफ.आई.आर. के लिए जाता है, आज हमने देखा कि 32 परसैंट abduction बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को proseculte करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जो बंद कमरे में बंद करके पीटा गया, मेरे पास फिर फोन आया। हम लोग accused के साथ आये थे, उसे पकड़कर लाये थे और मुझे पीटा गया, आप थाने आइये। जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं थाने गया। हमारे थाने में घुसते समय मुझे यह कहा गया कि विधायक की यहां जरूरत नहीं है। जो आई.ओ. था जिसने पहले दो व्यक्तियों को मारा। वह मेरे साथ गाली-गलौज करता है man handling करता है। संतरी मुझे गन प्वाइंट दिखाता है। बंदूक मेरे कनपटी से सटाता है। आखिर कैसे विश्वास होगा जनता को? मुझे ऐसा लगता है सर कि पुलिस की accountability तय होनी चाहिए। जब लोग थाने के अंदर थे, उनको बेरहमी से पीटा गया। 20 से 25 लोग बुरी तरह घायल हुए, क्या गलती थी उनकी? वे तो केवल एफ.आई.आर. कराने के लिए आये थे। अपनी मांग लेकर आये थे। जनता में गुस्सा है। लोग परेशान हैं। कैसे थाने जायेंगे। मुझे ऐसे लगता है सर कि पुलिस की accountability तय होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि Police Commissioner को बिल्कुल समन करना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कपिल भाई की बातों से कि उनको बुलाया जाये और उनको एक strict हिदायत दी जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि ये आदमी विक्टिम है। हम लोग कब तक विक्टिम रहेंगे? हम जनता की आवाज बनकर यहाँ आये हैं। जनता के साथ ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं अभी माननीय गुप्ता जी की बात सुन रहा था।

अध्यक्ष महोदय : संजीव जी कन्क्लूड करें।

श्री संजीव झा : दो मिनट सर। मुझे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो या दिल्ली पुलिस को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर एक भी बात उन्होंने नहीं रखी। मैं बिल्कुल इन लोगों से ये आशा रखता हूं कि आप दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच कड़ी बनकर रहेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली पुलिस जनता के प्रति accountable हो, इसके लिए आप सब लोग कोशिश करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह, दिल्ली कैण्ट।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं दिल्ली कैण्ट विधान सभा से संबंध रखता हूं। मैं यहाँ सदन में बैठे हुए सभी भाइयों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो दिल्ली कैण्ट विधान सभा है वह रक्षा मंत्रालय की बॉडी है, जिसके अंदर भारत सरकार के कायदे कानून के तहत काम किया जाता है। पिछले 8 महीने से वहाँ दिल्ली कैण्ट की जनता पानी से परेशान है। उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिसमें हर एरिया को बहुत अच्छी तरह कवर किया हुआ है। दिल्ली कैण्ट में रहने वाले लोगों को आज भी वहां पर बिजली के कनैक्शन उपलब्ध नहीं हैं। पीने का पानी नहीं है। सड़कें नहीं हैं, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं हैं। मैं चाहता हूं इस सदन के माध्यम से दिल्ली कैण्ट में रहने वाले, झुग्गी बस्ती में रहने वाले, गांव में रहने वाले उन सब लोगों का सहयोग किया जाये। सैकड़ों साल से वहां पर लोग रह रहे हैं। परन्तु उन्हें मालिकाना हक किसी प्रकार का नहीं है। आये दिन वहां पर तोड़-फोड़ की जाती है। जब सरकार चाहती है उसी टाइम वहां पर सीलिंग

की जाती है मकानों की। किसी गरीब आदमी के पास अगर पशुओं के नाम पर गाय-भैंस है तो उसको अपनी मर्जी से कैण्ट बोर्ड के माध्यम से उठवा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं दिल्ली पुलिस की करना चाहूंगा। दो महीने पहले दिन-दहाड़े एक व्यक्ति का मर्डर किया गया। आज तक दोषियों को, किसी को, नहीं पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस कोई बात नहीं सुनती है। अभी 22 तारीख को दिन-दहाड़े वहां पर एक व्यक्ति पर गोलियाँ चलाई गईं। अभी तक उसमें पुलिस की कार्रवाई या किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई की जाये। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ में जो हमारे बी. जे.पी. के साथ बैठे हुए हैं,

अध्यक्ष महोदय : सुरेन्द्र जी कन्क्लूड करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह : वे कड़ का माध्यम बनें। हम इतनी मजबूती के साथ आये हैं, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास जताया है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है। अगर आन्दोलन की जरूरत है तो दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य के लिए आन्दोलन करने के लिए भी तैयार है। मैं आप लोगों से यही आज अनुरोध करूँगा। आपका बार-बार धन्यवाद करूँगा कि आप लोग एक अपनी बात को भारत सरकार के सामने मजबूती के तौर पर, हक के तौर पर रखें, न कि अनुरोध के तौर पर। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश प्रधान। बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री जगदीश प्रधान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी आदरणीय माननीय

मंत्री जी श्री गोपाल राय और मनीष सिसोदिया जी ने जो अपना भाषण दिया, उसमें शिक्षा की बात कही। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और जो गोपाल राय जी ने कहा कि दिल्ली में समान विकास होना चाहिए, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। ये दिल्ली तीन तरह की दिल्ली है। एक अति पैसे वालों की, एक मिडियम दिल्ली और एक दिल्ली वो है जहाँ गोपाल राय जी की विधान सभा से नॉर्थ का एरिया है। इसमें करावल नगर विधान सभा, मुस्तफाबाद, गोकलपुरी और सीमापुरी आती हैं। जहाँ दिल्ली में विद्यालय हैं। मेरे विचार से कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते या न के बराबर आते हैं। कई जगह ऐसी हैं दिल्ली विधान सभा क्षेत्रों की कि जहाँ 5-7 लाख की आबादी एक विधान सभा में हो, और वहां केवल एक सेकेण्डरी विद्यालय हो, और एक सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबसे पहले प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाये, जहाँ विद्यालयों की कमी है। जहां प्राइमरी विद्यालयों की बात कही गयी। तो मैं तो उन प्रावेट विद्यालय वालों का शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने वहाँ छोटे-छोटे विद्यालय खोलकर वहां के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि मैं मुस्तफाबाद विधान सभा की बात कर रहा हूं कि वहां एक भी प्राइवेट सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय नहीं है। जो दूसरी विधान सभा के अंदर पड़ते हैं वे विद्यालय मनमानी फीस वसूल करते है। मनमाना डोनेशन लेकर उन बच्चों को वहां एडमिशन दिलाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो विद्यालयों के लिए जगह की पाबन्दी बनाई हुई है कि हजार मीटर होगी या दो हजार मीटर होगी या 4 हजार मीटर होगी, वहां उन क्षेत्रों में जहां सरकारी विद्यालय नहीं हैं, उनको कम से कम जगह में मान्यता दिलाने की कृपा करें।

जहां तक परिवहन समस्या की बात श्री गोपाल राय जी ने कही, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। आज भी दिल्ली में

कई विधान सभाएं ऐसी हैं जहां बसें नाम की चीज नहीं है, बच्चे यह नहीं जानते कि बस होती क्या है। मैं अपनी विधान सभा की बात कर रहा हूँ कि एक भी बस हमारी विधान सभा के अंदर नहीं आती है। रास्ते नहीं है, रास्ते के ऊपर एनक्रोचमेंट किया हुआ है लोगों ने। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप शायद करावल नगर, मुस्तफाबाद एक आध बार गये हैं और आपने वहां ट्रैफिक का क्या आलम होता है वो आपने देखा हुआ है अच्छे तरह से। तो उन विधान सभाओं को जो रास्ते रुके हुए हैं, भजनपुरा से लेकर करावल नगर तक, दयालपुर तक रोड़ चौड़ा हो गया है और दयालपुर के बाद शिव विहार से लेकर मुस्तफाबाद, ब्रजपुरी तक वो बीच में रुका हुआ है तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि ऐसे रास्तों को प्राथमिकता दी जाए ताकि वहाँ के बच्चे विश्वविद्यालय बसों से जा सकें और वहाँ बसों की सुविधा मिल सके।

जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कही। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में हम बी.जे.पी. के तीन विधायक यहाँ बैठे हैं हमारे, उसमें आपको पूरा सहयोग देंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो पूरी तरह से।

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, कनक्लूड करें प्लीज।

श्री जगदीश प्रधान : चलो आपने कहा, धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : मैं जगदीश जी का धन्यवाद कर रहा हूँ बहुत अच्छा पोजिटिव रास्ता उन्होंने अपनाया। एक बार मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बहन सरिता जी।

कु. सरिता सिंह : अध्यक्ष महोदय जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर रोहताश नगर विधान सभा से निर्वाचित होकर आई हूँ। बहुत ही आम लड़की

हूं। पाँच साल तक सड़कों पर आंदोलन किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि जब एक आम लड़की वहाँ पर जाती है अपनी पीड़ा को लेकर तो पुलिस उल्टे-सीधे सवाल पूछती है, पुलिस साथ नहीं देती और आज जब हम सब यहाँ इस सदन में बैठे हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को बिल्कुल न भूलें और वो याद रखिये और यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस सदन में हम सब यह जिम्मेदारी लें क्योंकि एक बेटी, एक बहन जो झुग्गियों में रहती है, जो घरों में रहती है उसको यह नहीं पता कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती। वो जब हमारे पास आती है तो एक भाव लेकर आती है कि मुझे हैल्प चाहिए, उस समय हम अपना हाथ हाथों में धरे नहीं बैठ सकते कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, दिल्ली पुलिस दिल्ली सदन की नहीं मानेगी इसलिए आपसे यह उम्मीद है, आपसे यह निवेदन है कि दिल्ली पुलिस को इस सदन के लिए जवाबदेही बनाया जाये क्योंकि जनता दिल्ली पुलिस से बहुत दुखी है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से बहुत दुखी है। जनता दिल्ली पुलिस से डरती है, आपकी बातों को उनसे कहने के लिए जब जाती है तो उनको लगता है कि अगर इनके पास जायेंगे तो हमसे उल्टे-सीधे सवाल पूछे जायेंगे और हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो जो यह डर है इस डर को मिटाने की जरूरत है और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस डर को उनके बीच से हटाएं। और इसीलिए जिस तरह कपिल भाई ने बोला कि कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाया जाये, उनको समन किया जाये, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाये यह सबसे बड़ी, गुप्ता जी इतनी देर से बहुत सारी चीजें गोल-मोल, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ एक निवेदन है कि बहुत सारी चीजें आप गोल-मोल तरीके से बोल रहे थे आप तीन साथी यहाँ बैठे हैं जो भाजपा के हैं केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आपको मिली है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी, प्लीज आप अपनी बात रखिये।

कु. सरिता सिंह : बिल्कुल, दिल्ली में दिल्ली सरकार सब कुछ करेगी पर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर आये, यह शायद ये तीन लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये शायद सब लोग इस चीज को मानेंगे कि यह आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर केवल चिंता, आश्वासन और चर्चा न करें, जनता ने यहाँ पर हमें काम करने के लिए भेजा है, दिल्ली की जनता ने हमें कार्य करने के लिए भेजा है जो कई सालों से दिल्ली में नहीं हुआ था तो यहाँ पर हम केवल चिंता, आश्वासन, आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति न करके कार्य की राजनीति करें, काम की राजनीति करें तो बस यही कहना चाहती हूँ। दिल्ली की महिलाएँ आधी आबादी हैं बहुत परेशान हैं दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है we should not be proud of this. This is a shame fact for Delhi and we all are representing Delhi here and, Sir, it is a request to you. कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज को अपने संज्ञान में लाइये और इसके लिए कार्रवाई करिये।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्रीमान मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने जो अपना मार्गदर्शन और सरकार के आगामी होने वाले कार्यक्रम के बारे में इस सदन को सूचित किया। सदन में भारी संख्या में मौजूद होकर उनके उस वक्तव्य को अच्छी तरह स्वीकार किया और उनका धन्यवाद करते हुए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की जो हालत है हम उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं हैं। 2013

और 2014 के अंतराल में केवल 35 परसेंट रेप के केसेस में बढ़ोतरी हो गई है यह उस समय की बात है जब देश में एक ऐसी सरकार का लोगों ने चुनाव किया और सब को दरकिनार करते हुए केवल एक सरकार को, केवल एक पक्ष को, केवल एक पार्टी को भारी बहुमत से जिता दिया। यह दिल्ली वही है जहाँ हर रोज 18 बच्चे अगवा किये जाते हैं और अगर उन बच्चों के अगवा होने की खबर के लिए अगर कोई जनप्रतिनिधि थाने जाता है तो उसके बजाय, बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करें उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। यह वही दिल्ली है जहाँ लगातार बहुत सारे जो सीरियस क्राइम हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रही है पर मुझे गर्व है कि मैं उस दिल्ली का वासी हूँ कि जहाँ 84 लाख दिल्ली की फोर्स तो है पर केवल 30 परसेंट जनता की सुरक्षा के लिए मौजूद है, बाकी बचा हुआ 70 परसेंट किन विभिन्न कार्यों में लगा है, सरकार की इस पर जिम्मेवारी है। मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली पर गर्व है दिल्ली पर गर्व इसलिए है कि जितने सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो कोई इन दिक्कतों का सामना नहीं करते क्योंकि वो इससे महफूज हैं अगर किसी लड़की का बलात्कार होगा, किसी बेटी का बलात्कार होगा, तो वो केवल लोअर दर्जे की होगी वो न तो किसी बड़े पद पर रहने वाले अधिकारी की है, न किसी मंत्री की है, न किसी एम. पी. की है, न किसी एम.एल.ए. की है क्योंकि पुलिस उनकी मदद के लिए सदा तैयार है। बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत शर्म आती है कि वो दिल्ली पुलिस जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए आज बड़े-बड़े वी.आई.पीज, मंत्री और उन लोगों की सुरक्षा कर रही है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर न होकर समाज के प्रति जिम्मेवारी होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली पुलिस को

इस राजधानी की सरकार के अधीन होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम सारे मिलकर, हमारा कर्त्तव्य जो है हम उसको पूरा करने की दिशा में रखें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और मैं निवेदन करता हूँ अपने तीन यहाँ इस साइड में बैठे हुए महानुभावों से यहाँ प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, पिछले सत्रों में मौजूद रहे हैं, पूर्ण राज्य दिल्ली को मिले, जिसके वो सदा हमेशा से हितैषी रहे हैं, उनकी आवाज पहले बुलंद थी, मुझे अब भी लगता है कि उनकी आवाज इस दिशा में जरूर बुलंद होगी और वो भी हमारे साथ मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमारे साथ प्रयत्नशील रहेंगे। वो एक ऐसा कदम होगा जब हम दिल्ली से करप्शन को, समाज में फैले हुए जो रोग हैं चाहे वो रेप का हो, चाहे बच्चों की अगवा करने का हो उससे हम निजात पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद मदन जी। श्रीमान सोमनाथ भारती।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय उपराज्यपाल जी का जो अभिभाषण है बड़ी concise रूप में पूरी रूपरेखा जो है सरकार की यह व्याख्यान करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी सटीक और सुडौल भाषा में लिखी हुई सारी चीजें कैसे बिजेन्द्र गुप्ता जी को समझ में नहीं आइ ं। अभी मेरे साथियों ने और गोपाल भाई ने जो बात कही इस सदन में, मेरी आँखें नम हो आईं कि जिन क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे आशा है कि जिस भाषा में हमारे साथियों ने आज सदन में अपनी भावनाएँ व्यक्त करी हैं उसके साथ उनके जो अधूरे सपने रह गए हैं उसको हम पूरा कर पायेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें पुलिस रिफार्म्स पर बड़ी तन्मयता से कहना चाहता हूँ कि एक तो थाना में जब हम पिछली बार सरकार में थे तो थाना लेवल कमेटी बनी थी उसके अंदर मैंने एक प्रस्ताव मूव किया था कि हर थाने के अंदर चूंकि trust-deficit बहुत ज्यादा है जनता और पुलिस के बीच में, हर थाने में अगर public interaction places designate हो जाये और उन places को सी.सी.टी.वी. से मॉनिटर भी करे और रिकार्ड भी करे तो मैं चाहता हूँ कि यह सदन आपके जरिये इस बात को दिल्ली पुलिस के पास पहुँचाई जाये कि हर थाने के अंदर जो trust-deficit है जनता और पुलिस के बीच में उसकी भरपाई करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम यह होगा कि pablic interaction places जैसे कि FIR Counter हो गया Investigation Room है एक, इंक्वायरी रूम है SHO Room है, इन सभी जगहों को सी. सी.टी.वी. से मॉनिटर भी करें, रिकार्ड भी करें। जो मेरे साथ जुड़ा जो एक काण्ड चला आ रहा है, ड्रग टैफिकिंग का - खिड़की एक्सटेंशन का। उस वक्त कहा गया कि मैंने पुलिस को नहीं बताया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पिछले 2 महीने पहले मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखा है कि उस जगह पर ये चीज फिर से पनप रही है। और मेरे पास आज तक कोई जवाब नहीं आया है। दिल्ली पुलिस से कोई जवाब नहीं आया है कि जो वहां पर फिर से पनप रही और घटना घटने वाली है, इन फैक्ट बीस एक चीजें वहां पर फिर से होनी शुरू हो गयी हैं। इसका क्या होगा, कैसे होगा? इसलिए बहुत साथियों ने जो आज विचार प्रकट किए हैं कि दिल्ली पुलिस की एकाउन्टेबिलिटी इस सदन के प्रति सुनिश्चित होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जनता हमारे पास आती है। जैसे हमारी साथी सदस्य सुश्री सरिता सिंह ने कहा कि जनता को नहीं मालूम कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है।

जब पिछली बार अरविन्द जी धरने पर बैठे थे, तब बहुत लोगों को पहली बार, पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम पड़ा था कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार

के अधीन नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर हम जनता को पूर्णतया जिस मैनडेट के साथ उन्होंने हमें चुना है, अगर सेवा करनी है तो दिल्ली पुलिस की एकाउन्टेबिलिटी सुनिश्चित होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक शर्मसार करने वाली जो घटना है, उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहाँ कि आज भी ओपन डिफेकेशन हो रहा है, खुले में शौच के लिए लोग जा रहे हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ– मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र वहां भी चार ऐसी लोकेशन्स हैं, जहाँ कि महिलाओं को आज भी खुले में/ओपन में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। यह शर्मसार करने वाली घटना है। मैं चाहता हूं कि इन जगहों पर तुरन्त एम.सी.डी. के जरिए टॉयलेट उपलब्ध कराये जायें, जिससे कि इसको रोका जाये।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, क्न्क्लूड कीजिए। ...**(व्यवधान)**... बिजेन्द्र जी आप बीच में न बोलें प्लीज, उन्होंने अपनी बात रखी है। आप बीच में टोका-टोकी करेंगे, यह उचित नहीं। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : वह कालोनी किसके पास है, यह भी तो देखना पड़ेगा। चलिए

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अभी जो स्वच्छता अभियान के नाम पर फ्रॉड चल रहा है, पूरी दिल्ली में न तो डस्टबिन्स अवेलेबल हैं, न टायलेट्स अवेलेबल हैं। ये जो हजारों-करोड़ खर्च किए जा रहे हैं एडवर्टीज के ऊपर, उस पर न खर्च करके अगर हम पूरी दिल्ली में मैप करके डस्टबिन्स कहाँ कहाँ लगने चाहिए, टॉयलेट कहां कहा बनने चाहिए, अगर इसके ऊपर काम हो तो बड़ा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं पिछली बार कानून मंत्री था, एक प्रपोजल मूव किया था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अगर जनता को वास्तव में न्याय मिल सके, उसके लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स सारे वीडियो रिकॉर्ड हों, वह एक कार्य और अधूरा हमारा रह गया है, उसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उसको पूरा किया जाये। सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स वीडियो रिकॉर्ड हों, जिससे कि वहां पारदर्शिता आ सके। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। कुछ और सदस्यों ने बोलने के लिए आग्रह किया था लेकिन समय के अभाव में मैं उनसे माफी चाहता हूँ। अनिल वाजपेयी जी ने, ओम प्रकाश शर्मा जी ने, श्री पंकज पुष्कर जी ने और श्रीमती बंदना जी ने बोलने की इच्छा जताई थी। समय का अभाव है। अगली बैठकों में जब भी होगा। मैं उन्हें प्राथमिकता दूंगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि वे अपना वक्तव्य दें।

मुख्यमंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण, सम्मानित सदस्यो, आज माननीय उपराज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में आने वाले 5 सालों के अंदर हम किस किस्म की दिल्ली देखना चाहते हैं, और उसे कैसे हम लोग अचीव करेंगे, इसका उन्होंने बहुत अच्छा खाका प्रस्तुत किया। मुझे याद है आज से पूरे एक साल पहले हम लोग यहीं बैठे थे, हमारे यहां पर 28 सदस्य थे, उधर सामने बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने मिलकर जिस तरह से दो दिन तक इस विधान सभा के माइक तोड़े, फाइलें फाड़ीं और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हम 40 हैं, हम 40 हैं, हम 40 हैं। आज पूरे एक साल के बाद नियति ने, भगवान ने इस देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उन 40 से उनको तीन कर दिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि गुरूर किसी का

नहीं बचता, अहंकार किसी का नहीं बचता, घमण्ड किसी का नहीं बचता। और ये हम सब लोगों को भी बड़ा ध्यान रखना है। मैं बार-बार सब लोगों को बोलता हूं कि आज हम 67 हैं। हमें भी बड़ा ध्यान रखना है, हमें भी अहंकार नहीं करना है। जनता ने बहुत भरोसा करके, जनता ने बहुत उम्मीद करके हम लोगों को चुना है और हमें पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर जनता की सेवा करनी है। जनता ने हमें वोट क्यों दिया? ये जब मैं सोचता हूं तो मोटी-मोटी तीन बातें मेरे सामने आती हैं। पहली चीज मई के महीने में जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा था। आज 8-9 महीने में क्या हो गया? तो जनता कह रही है कि हमें भाषण नहीं, हमें काम चाहिए। तो हमें भी ये ध्यान रखना है आने वाले समय में हम सब लोगों को बोलना कम है, काम ज्यादा करना है। भाषण कम देने हैं। भाषण से हम एक बार दो बार तीन बार तो लोगों को लुभा लेंगे लेकिन फिर जनता कहती है कि भाषण से पेट तो नहीं भरता, घर तो नहीं चलता, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं होती। तो भाषण नहीं, हमें काम पर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज दिल्ली की जनता को वो 49 दिन याद थे। बार-बार दिल्ली की जनता में जहाँ भी जा रहा था, मैं खूब घूमा दिल्ली के अंदर जहाँ भी जा रहा था, दिल्ली की जनता कह रही थी कि वे 49 दिन वापस चाहिए। उन 49 दिन के अंदर लोगों ने जिस किस्म का चमत्कार देखा दिल्ली के अंदर वो जनता को वापस चाहिए। तो मोटे-मोटे तौर पर दिल्ली की जनता तीन चीजें याद कर रही थी। बिजली सस्ती हो गई थी जी। बिजली के रेट आधे हो गये थे। पानी सस्ता हो गया था, पानी मुफ्त हो गया था, दिल्ली से भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया था। बिजली और पानी कुछ दिनों में सस्ता करने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पर किया था। दिल्ली की जनता ने जो हमें वोट दिया, उसका हम सम्मान करते

हैं और जैसे हम कहते हैं : जो कहा सो किया। तो दिल्ली में बिजली और पानी बहुत जल्द सस्ते होंगे। दूसरा जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है। मुझे लोग बताते हैं कि सरकार बनी थी, उसके बाद ही भ्रष्टाचार में काफी कमी आ गयी है दिल्ली के अंदर। लेकिन अभी 40-50 प्रतिशत की कमी आई है। जल्दी ही वो टेलीफोन लाइन शुरू करेंगे। जिस टेलीफोन लाइन की वजह से लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करने चालू किए। और लोगों के हाथों में ताकत दे दी थी कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करना। उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें लाकर दे देना। उस अफसर को हम सजा देंगे। वही टेलीफोन लाइन इस बार और सुचारु रूप से, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। और तैयारी की जा रही है। और तीसरा कारण जिसकी वजह से जनता ने हमें वोट दिया, वह यह है कि जो हमने पूरी दिल्ली का दिल्ली डॉयलॉग के जरिए खाका पेश किया पूरी दिल्ली के सामने, वह खाका दिल्ली की जनता को बहुत पसंद आया। उन सारे वादों को, उस सारे विज़न को और आज उपराज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिल्ली का खाका प्रस्तुत किया, उसे हम सब लोगों को पूरा करना है। गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में दिल्ली में पानी की समस्या बहुत गहरी रहती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से, सभी पार्टियों के सदस्यों से आप सब से भी एक निवेदन करता हूं कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या तीन तरह की हो सकती है : एक तो वो जहां पर पाइप है, लेकिन पानी कम आता है। 15 मिनट आता है, 10 मिनट आता है। आता ही नहीं है कई कई दिन तक। दूसरा वो जहां पानी गंदा आता है और तीसरा वो जहां पानी की पाइप लाइन ही नहीं है, और टैंकर से आता है। तो अगर आप अगले हफ्ते 15-10 दिन के अंदर अपनी अपनी क्षेत्र की स्पेसिफिक कॉलोनी वाइज समस्या हमें बता दें तो उसका

हम सब लोग मिलकर, चाहे वह बी.जे.पी. का क्षेत्र हो या आम आदमी का क्षेत्र हो, हम सब लोग मिलकर उसका समर प्लान तैयार कर सकते हैं ताकि हमारी दिल्ली की जनता को उस समय तकलीफ न हो।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : प्लान तो तैयार हो जाना चाहिए था अब तक।

मुख्यमंत्री : सर आप कुछ दे तो दीजिए। अच्छा चलिए, बैठ जाइये बैठ जाइये। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र गुप्ता जी, यह प्लान का हिस्सा है कि विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बार-बार बीच में टोकते हैं, ये उचित नहीं है।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। जो मेरी ड्यूटी है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भली-भांति जानता हूँ, आप पहली बार नये सदस्य बने हैं, मैं पाँच साल रह चुका हूँ। देखिये, अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा। बिजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये, प्लीज।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। प्लीज आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : xxxx

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी जो भाषा बोल रहे हैं, वो सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए। आप यह असंसदीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप बैठ जाइये। प्लीज। आप विघ्न डाल रहे हैं, आप बैठ जाइये। कल की कार्यवाही की आज चर्चा कर रहे हैं कल बात करते। आप बैठ जाइये। जगदीश जी, आप सीट पर चलिये। बिजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। यह सदन की गरिमा का बहुत बड़ा अपमान है, ओम प्रकाश जी, बैठ जाइये। मैं बहुत impartial हूँ आप बैठिये। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं बीच में कोई टोकेगा नहीं। मैं impartial हूँ। मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं बीच में कोई बोलने का अधिकार नहीं है। सदन की गरिमा को बनाकर रखें। जगदीश जी, बैठिये प्लीज। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं किसी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है। आप बैठिये। आप बीच में टिप्पणियाँ कर रहे हैं। आप प्लीज बैठ जाइये।

मुख्यमंत्री : दोस्तो, इस बार हम लोग बजट जब बनायेंगे, एक नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे और उसको पायलट बेसिस पर किया जायेगा। जैसे बजट जब बनता है तो कैसे बनता है, पी.डब्ल्यू.डी. वाले आते हैं कहते हैं जी पिछली साल हमारा फलाना, फलाना इतने हजार करोड़ का बजट था। मान लो पाँच हजार करोड़ का बजट था, इस बार दस परसेंट बढ़ा दो, 55 सौ करोड़ करा

xxxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही से निकाले गए।

दो। कोई और विभाग आयेगा वो कहेगा जी पिछली बार हमारा इतने हजार करोड़ का था, दस परसेंट बढ़ा दो इतने करोड़ कर दो। अब वो पीतमपुरा में रहने वाला आदमी या सरिता विहार में रहने वाला आदमी या ओखला में रहने वाला आदमी या मुंडका में रहने वाला आदमी, वो कहता है जी मेरी गली नहीं बन रही, यह गली कैसे बनेगी। तो वो पी.डब्ल्यू.डी. के 55 सौ करोड़ तो आ गये, साढ़े पाँच हजार करोड़ तो आ गये लेकिन उस आदमी की गली तो नहीं बनी और वो फिर जब जाता है तो कहते हैं जी पैसा नहीं है अभी, अब यह पैसा इतना सारा हाई-फाई सारे डिपार्टमेंट अपना बजट बना लेते हैं वो पैसा जाता कहाँ है, किसी को पता नहीं चलता। तो इस बार हमने सोचा है कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो कि दुनिया के कुछ और शहरों में भी ट्राई किया गया और उसके बड़े अच्छे नतीजे हुए कि क्यों न बजट जनता बनाये इस बार। तो पाँच से दस विधान सभाओं में हम यह एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें उन विधान सभाओं में, उन विधान सभाओं के कुछ छोटे-छोटे मौहल्ले में बांट दिया जायेगा, हर मौहल्ले के नागरिकों की मीटिंग होगी और नागरिक कहेंगे कि उनको क्या-क्या चाहिए। मान लीजिए फलानी-फलानी कालोनी के नागरिकों ने मिलकर कहा जी हमारे फलाने पार्क की दीवार टूटी हुई है, वो ठीक करा दो। किसी ने कहा जी वो बत्ती नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइट की वो ठीक करा दो। वो लिखा जाएगा और उस सब को कम्पाइल करके और उसको विधान सभा में पेश किया जाएगा और विधान सभा में जब पास होगा, उसके पार्क का बजट यहीं से पास होकर जाएगा, वो फिर पी.डब्ल्यू.डी. या उस पर कोई jurisdiction नहीं है कि उस बजट को इधर का उधर कर दें। इसको हम पाँच से दस

विधान सभाओं में इस बार करने की कोशिश करेंगे कि जनता बजट बनाये और जो जनता बजट बनायेगी उसको यह विधान सभा, हम लोग जनता से हैं कल को जनता हम लोगों को वोट नहीं देगी, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग कुछ नहीं हैं तो जनता जो हमको डायरेक्शन देगी हम बार-बार पाँच साल में एक बार, हम लोग जनता के बीच में नहीं जायेंगे, हम रोज जनता के बीच में जायेंगे, रोज जनता से जाकर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए।

मैं इस सदन की जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले साल जब हम सरकार छोड़कर गये थे, दिल्ली को फायदे में छोड़कर गये थे, नफे में छोड़कर गये थे, पोजिटिव में छोड़कर गये थे। पिछले नौ-दस महीने में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन के जरिये दिल्ली को चलाया और आज 4350 करोड़ का टारगेट से कम पैसा इकट्ठा हुआ है, अगले एक महीने के अंदर हमें खर्चों में काफी कमी करनी पड़ेगी ताकि इस टारगेट को, जो टारगेट कम हुआ है, तो जो ये लोग कहते हैं सरकारी चलानी आती है, सरकारी चलानी आती है इनको, हमें पैसा चाहिए, पिछली साल हम लोगों ने रिकार्ड कलैक्शन किया था टैक्स का। मैं माननीय सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोगों ने बिना रैड मारे टैक्स इकट्ठा किया था, बिना व्यापारियों को परेशान किये, व्यापारियों को गले लगा लिया और व्यापारियों को लगा कि इनकी सरकार पैसे खाती नहीं है और एक-एक पैसे का जो हम टैक्स देंगे वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। लोगों ने बढ़-चढ़कर टैक्स दिया था और पिछले आठ-नौ महीने का डेटा है कि दिल्ली के अंदर हर हफ्ते 40 से 60 रैड व्यापारियों के ऊपर हो रही हैं तो कल या परसों माननीय वित्त मंत्री जी ने वैट कमिश्नर को बुलाकर साफ-साफ कहा है कि यह जो रूटीन रैड हो रही है 40 से 60 यह बंद की जाए, यह रैड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए व्यापारियों के ऊपर अगर किसी व्यापारी

के बारे में स्पेसिफिक जानकारी मिलती है कि उसने टैक्स की चोरी की है और यह चोरी की है स्पेसिफिक इनफोर्मेशन के ऊपर तभी उस व्यापारी के ऊपर रैड की जाएगी अदरवाइज यह रूटीन रेड जो 40 से 60 हर हफ्ते होती है, यह सारी रैड बंद की जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम जनता को गले लगा लेंगे, व्यापारियों को गले लगा लेंगे तो आने वाले समय में बिजेन्द्र गुप्ता जी, अध्यक्ष महोदय के जरिये मैं कहना चाहता हूँ कि 30 हजार करोड़ तो क्या, दिल्ली की जनता 60 हजार करोड़ हम लोगों को देगी। आज, सर, दो मिनट ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आप हर वक्त टीका टिप्पणी करते हैं। आप बार-बार टीका-टिप्पणी करते हैं। आप बैठिये। उनका पूरा उत्तर सुन लीजिए। शांतिपूर्वक सुन लीजिए। आप टीका-टिप्पणी कर रहे हैं उसके ऊपर। आप उनको बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं। बिजेन्द्र जी, यह उचित नहीं है। देखिये, आप सदन को ...**(व्यवधान)**...

मुख्यमंत्री : एक एक्सपेरिमेंट हम लोग इस बार करना चाह रहे हैं

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा माइक भी बंद कर देते हैं मुझे बोलने भी नहीं देते हैं, यह कौन सा लोकतंत्र है। अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : आप जितना समय सदन का खराब कर रहे हैं और सदन का मैक्सिमम समय आपने लिया है।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। इस पर तो इजाजत दीजिए। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं मैंने बोला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं सुनाई दिया, मुझे सुन लेने दीजिए उनका पूरा भाषण। आप बैठिये पहले।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना अनुरोध करूँगा मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने बोला है तो उसको एड करवा दीजिए, बस इतना ही तो। आपने प्रमाण माँगा था ना, प्रमाण मैंने पेश कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया। अब मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए।

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम एक बार और...एक एक्सपैरीमैन्ट दिल्ली के अंदर...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं न?

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आपने कार्यवाही से निकलवाये कुछ शब्द। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, ये कोई भी मर्यादित व्यवहार नहीं है। आप फिर बार-बार ये कहेंगे...

...(व्यवधान)...

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : आपने कहा है प्रमाण दीजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ये कहा है, उनको अपना भाषण देने दीजिए। अगर भाषण में..

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सुना है न?

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना अनुरोध है कि वे कह दें कि मैंने नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री बिजेन्द्र गुप्ता : मैंने जो बोला है..

अध्यक्ष महोदय : बिजेन्द्र जी, आपने अपनी बात बोल दी। वे सुन चुके हैं। उनको जो उत्तर देना होगा, उसका उत्तर देंगे। उनको कन्क्लूड करने दीजिए।

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक एक्सपैरीमैंट और दिल्ली के अंदर हम शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक अपने अफसर बहुत बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे, व्यवस्था में गड़बड़ थी। ये व्यवस्था कुछ किसी को नया करने का मौका नहीं दे रही थी। इस बार हम लोग... जैसे हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफर पोसिटिंग में क्या होता है। सिफारिशें आती हैं। ये हम सुना करते थे। पहले पैसा चला करता था अफसरों की, कर्मचारियों की पोस्टिंग में। इस बार हमने तय किया कि कुछ विभागों के हेड ऑफ दि डिपार्टमैन्ट जो हैं, उसके ऊपर एक नया एक्सपैरीमैन्ट किया जाये। एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं और उस टारगेट को पब्लिसाइज करते हैं और कहते हैं भई, इस टारगेट को पूरा

करने के लिए अफसर प्लान बनायें और प्लान लेकर सरकार के पास आयें। जिस अफसर के पास उस टारगेट को पूरा करने का सबसे बढ़िया प्लान होगा, उस अफसर को उस डिपार्टमैन्ट में पोस्टिंग दी जाएगी और उसके काम में कोई दखलअन्दाजी नहीं की जायेगी और उसको पूरा टैन्योर दिया जायेगा। समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जायेगी। ऐसा भी न हो कि एक साल दे दिया और एक साल में उसने पूरा मट्ठ मार दिया। वह भी नहीं होना चाहिए। समय-समय पर समीक्षा की जायेगी। अगर वो टारगेट पर सही चल रहे हैं। तो ईमानदारी और एफिशिएन्सी... इसको रिवॉर्ड किया जायेगा। आज दिल्ली में नई सरकार बनी है। पिछले 10-15 साल में, पिछला एक साल छोड़ दें तो उससे पहले 15 साल तक काँग्रेस की सरकार थी। जिस दौरान पॉवर सैक्टर में प्राइवेटाइजेशन किया गया। कई सारी घटनाएं घटीं पॉवर सैक्टर में। दिल्ली की जनता के सामने ये रखना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में आज पॉवर की क्या सिच्युएशन है। तो सरकार जल्दी पॉवर सैक्टर के ऊपर एक ह्वाइट पेपर लेकर आयेगी और दिल्ली की जनता को बताएगी कि हमने कहाँ से शुरुआत की और अगले 5 साल में क्या क्या करने जा रहे हैं। ये ह्वाइट पेपर दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

तो अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जो कुछ बातें कहीं, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी सरकार का पूरा प्लान बताया, दिल्ली का विजन बताया और मैं उनके धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत एवं श्री प्रवीण कुमार द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव कि यह सदन माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 को दिए गए अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हाँ कहने के बाद)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

इसकी सूचना माननीय उपराज्यपाल महोदय को पहुँचा दी जाएगी।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बिजेन्द्र गुप्ता तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेन्सियों, विधान सभा परिसर में कार्यरत डिविजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। विधान सभा की कार्यवाही को मिडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभा पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है। अब हम सभी राष्ट्र गान के लिए खड़े होंगे।

(राष्ट्रगान जन-गण-मन)

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

विषय-सूची

सत्र01	मंगलवार, 24 फरवरी, 2015/फाल्गुन05, 1936 (शक)	अंक-02

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	अध्यक्ष द्वारा घोषणा	3–4
3.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्र (उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति)	4–17
4.	निधन सम्बन्धी उल्लेख	18–23
	1. श्री जनार्दन गुप्ता, पूर्व सदस्य, महानगर परिषद (1966 एवं 1970)	
	2. श्री अमरनाथ मल्होत्रा, पूर्व सदस्य, महानगर परिषद (1977–1980)	
	3. श्री सुनील कुमार वैद्य, पूर्व सदस्य, चतुर्थ विधान सभा (2008–2013)	
5.	उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान	23–93